DD
RNI No. DLHIN/25/A2321
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र
दिव्य दिल्ली
वर्ष: 01, अंक: 25, पृष्ठ: 08
infodivyadelhi@gmail.com
शनिवार, 04 अक्टूबर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi
तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री सूर्योदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

अब पूरे देश में वोटर लिस्ट से हटेंगे मृतकों के नाम

नई दिल्ली
सभी राज्यों में निकट भविष्य में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर में बिहार जैसी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, जहां लाखों मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग का मानना है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के आंकड़ों को चुनाव मशीनरी से जोड़ने की प्रणाली स्थापित होने के बाद मृत लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने का मुद्दा सुलझ जाएगा। बिहार में एसआइआर शुरू होने से पहले राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे। प्रक्रिया के बाद, एक अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में 7.24 करोड़ मतदाता रह गए। यानी लगभग 65 लाख नाम हटा दिए गए, इनमें 22 लाख मृत व्यक्ति भी शामिल थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में पहचाने गए 22 लाख मृत मतदाताओं की मृत्यु हाल में नहीं हुई थी बल्कि उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जिसका रिकार्ड दर्ज नहीं किया गया था। सीईसी ने कहा कि पिछले सामान्य पुनरीक्षण के दौरान गणना फार्म हर घर में नहीं दिए गए थे। जब तक लोग अपने परिवारों में हुई मौतों की सूचना नहीं देते, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के पास जानकारी नहीं होती। गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन तंत्र मृतकों और स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने में अधिक सतर्क रहता है। निर्वाचन प्राधिकरण अब रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया (आरजीआइ) से मृत्यु पंजीकरण डाटा इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को समय पर जानकारी मिलेगी। इससे मतदाता सूची अधिक त्रुटि मुक्त होगी। डाटा जोड़ने की व्यवस्था स्थापित होने पर मृतक व्यक्तियों के नाम बने रहने की स्थिति समाप्त हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली
बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर जारी संग्राम के बीच प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर विपक्षी पार्टियों ने खामोशी रखते हुए भले ही तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मगर इसमें संदेह नही कि दशहरा के बाद विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में हुई गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को अपने सवालों के साथ कसौटी पर कसेगा। कांग्रेस समेत बिहार में विपक्षी खेमे के अन्य दलों ने खास तौर पर अपने चुनावी तथा कानूनी विशेषज्ञों को ड्राफ्ट तथा अंतिम मतदाता सूची के विरोधाभासी पहलुओं से लेकर जोड़े या काटे गए नामों की संख्या समेत अन्य पहलुओं का गहराई से अध्ययन करा रहे हैं।

विपक्ष ने एसआईआर पर उठाए गंभीर सवाल

विपक्षी दल सात अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनेवाली सुनवाई से पहले अंतिम मतदाता सूची में हुई कथित गड़बड़ियों को सामने लाने की पूरी तैयारी में हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर पहले ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ले जा चुके विपक्षी दल अब अंतिम मतदाता सूची में काटे और जोड़े गए नामों से लेकर इस दौरान पूरी प्रक्रिया की खामियों को उजागर कर चुनाव आयोग को घेरने को लेकर आश्वस्त हैं। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर हमलावर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अंतिम मतदाता सूची को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के प्रश्न पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतकार ने कहा कि यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर विषय है और बिना आकलन किए तात्कालिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। पार्टी के चुनावी तथा डाटा विशेषज्ञ बिहार अंतिम सूची का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। अभिषेक सिंघवी एसआईआर के पूरे मसले पर पार्टी की सियासी और कानूनी रणनीति की सीधे निगरानी कर रहे हैं।

केंद्र ने दी राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की फसल प्रणालियों और आहार में दालों का विशेष महत्व है।
देश दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है।

मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय अपमान बर्दाश्त नहीं करते: पुतिन

सोची
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में आयोजित वाल्दाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए यह कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए, तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची

रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है, तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देश में लोग अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी तेल के बिना दुनिया की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और यदि इसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो तेल की कीमतें प्रति बैरल 100 डॉलर से भी ऊपर बढ़ सकती हैं। पुतिन ने मोदी का दोस्त बताते हुए कहा कि वह उनके साथ भरोसे के साथ बातचीत कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दिसंबर की शुरूआत में होने वाली अपनी भारत यात्रा को लेकर खुशी जताई। उन्होंने अपनी सरकार को यह भी निर्देश दिया कि भारत के बड़े पैमाने पर कच्चे तेल खरीदने की वजह से जो व्यापार असंतुलन बना है।

आरबीआई का सर्वे: महंगाई को लेकर लोगों की चिंता घटी

नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा सर्वे में देशवासियों को महंगाई और कीमतों में दबाव पहले के मुकाबले कम लग रहा है। सितंबर 2025 के इन्फ्लेशन सर्वे में लोगों ने खाद्य वस्तुओं से लेकर सेवाओं तक, लगभग सभी क्षेत्रों में कीमतों के दबाव में कमी बताई है। हालांकि वर्तमान में महंगाई की धारणा में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखी गई है, लेकिन आने वाले महीनों में महंगाई की उम्मीदें भी घटी हैं, जिससे आमजन को राहत की उम्मीद जगी है।

क्या कहा गया सर्वे में?
आरबीआई के ताजा सर्वे में सामने आया है कि देश के आम लोग अब

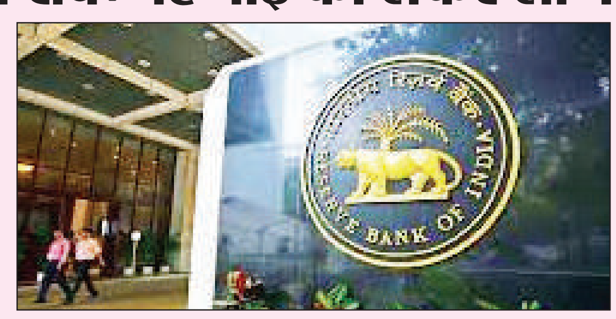

खाद्य पदार्थ, गैर-खाद्य वस्तुएं, मकान और सेवाओं की लागत में पहले के मुकाबले महंगाई का असर कुछ कम महसूस कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान महंगाई की धारणा थोड़ी बढ़ी है और यह 7.4% हो गई है, जो पिछले सर्वे की तुलना में 0.2% अधिक है। साथ ही सर्वे में ये भी बताया गया कि अगले तीन महीनों के लिए लोगों की महंगाई की उम्मीदें 8.3% से घटकर 8.1% पर आ गई हैं। वहीं, एक साल आगे की उम्मीदें भी घटकर 8.7% रह गईं, जो पहले 9.0% थीं।

क्या कहते हैं आंकड़ें?
बता दें कि सर्वे में बताया गया कि आने वाले तीन महीनों में 77.8% लोगों ने कीमतें बढ़ने की बात कही, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 79.5% था। एक साल के नजरिए से 86.8% लोगों को कीमतें बढ़ने की आशंका है, जो पहले 88.1% थी। ऐसे में सिर्फ 7.0 प्रतिशत जो कि 25 साल से कम उम्र के लोगों ने सबसे कम महंगाई महसूस की। वहीं 60 साल से ऊपर के लोगों ने इसे 7.9% बताया।

इसके अलावा कोलकाता में सबसे ज्यादा महंगाई महसूस की गई, 10.5%, इसके बाद मुंबई (8.5%) और दिल्ली (8.0%) रहे। गौरतलब है कि सर्वे को लेकर आरबीआई ने साफ किया कि यह सर्वे सिर्फ लोगों की राय दिखाता है।

सबरीमाला: सोने की परत चढ़ाने मामले में विस्तृत जांच पर अड़ा टीडीबी

तिरुवनंतपुरम
केरल के सबरीमाला मंदिर में 1998 से 2025 तक द्वारपालक मूर्तियों पर चढ़ाई गई सोने की परत की जांच अब केरल हाई कोर्ट की निगरानी में हो सकती है। इस बात की जानकारी त्रावणकोर देवस्वं बोर्ड (टीडीबी) अध्यक्ष पीएस प्रसंथ ने दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। इस विसतृत जांच में सोने की मात्रा और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड के स्थायी वकील को इस मामले में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट के पूजा अवकाश के बाद यह याचिका दायर की जाएगी।

भारत-फ्रांस के बीच रक्षा साझेदारी की मजबूती पर जोर

नई दिल्ली
भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (एफएसएफ) के बीच 22वीं एयर स्टाफ वार्ता का तीन दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन चर्चाओं में संयुक्त प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, विचारों का आदान-प्रदान, पेशेवर सैन्य शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। चचाओं का उद्देश्य संचालनात्मक समन्वय को मजबूत करना और दोनों वायु सेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना

था। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल एसके तलियान और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के ब्रिगेडियर जनरल निकोलस चांबाज ने की, जो उच्च स्तर की भागीदारी और गहरे रक्षा सहयोग के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एयर स्टाफ वार्ता भारत और फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे वे आपसी सहयोग को बढ़ा सकते हैं, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान कर सकते हैं और एयरोस्पेस और रक्षा में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और विकसित कर सकते हैं।

भारत व फ्रांस के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी
विदेश मंत्रालय के अनुसार, "भारत व फ्रांस के बीच एक मजबूत और ठोस रक्षा साझेदारी है। इसमें 'आत्मनिर्भरता' का तत्व बढ़ रहा है।

दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा वार्षिक रक्षा संवाद (रक्षा मंत्री स्तर) और रक्षा सहयोग पर के तहत की जाती है।"

पीएम मोदी के मुरीद हुए डच कंपनी के अधिकारी

पीएम मोदी से सीखने की दी अन्य कई नेताओं को नसीहत

नई दिल्ली
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी की तारीफ अब डच सेमीकंडक्टर दिग्गज एएसएमएल के वैश्विक जनसंपर्क मामलों के कार्यकारी उपाध्यक्ष, फ्रैंक हेम्सकेर्क ने की है। उन्होंने बताया कि एएसएमएल के सीईओ ने हाल के दिनों में ही पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं तक पहुंच आसान नहीं है, जबकि भारत के पीएम के साथ ऐसा नहीं है।

एएसएमएल के सीईओ ने की थी पीएम मोदी से मुलाकात
दरअसल, हाल के दिनों में ही डच सेमीकंडक्टर दिग्गज एएसएमएल के सीईओ ने पीएम मोदी से करीब 2 घंटे की मुलाकात की थी। उन्होंने

बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल उनकी बात सुनी, बल्कि कंपनी से प्रतिक्रिया देने का आग्रह भी किया।

पीएम मोदी के मुरीद हुए एएसएमएल के अधिकारी
एएसएमएल के अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे (कंपनी के सीईओ) कहा कि आप बहुत मिलनसार हैं, मुझे बताएं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बता दें कि बातचीत के दौरान फ्रैंक हेम्सकेर्क से पूछा गया कि क्या सभी नेताओं के साथ मिलना आसान होता है, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि यह हमेशा आसान नहीं होता। आम तौर पर तो व्हाइट हाउस में किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलना, कमिश्नर से मिलने से कहीं ज्यादा आसान है।

'पीएम मोदी से सीखना चाहिए'
उन्होंने कहा कि यूरोपीय नीति निमार्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजनीतिक नेताओं को उन कंपनियों के साथ बैठना चाहिए जो निवेश कर रही हैं। वहीं, इसी बातचीत के दौरान एएसएमएल के फ्रांसीसी एआई फर्म मिस्ट्रल के साथ हाल ही में हुए 1.3 बिलियन यूरो के सौदे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह आसान है क्योंकि यह एक यूरोपीय कंपनी है और हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं।

नागरिक विद्रोह है पीओके का आंदोलन, रुकने वाला नहीं: आगा

पाकिस्तान में पीओजेके के नागरिकों को दोयम दर्ज का माना जाता है

पीओजेके
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में शुरू हुआ आंदोलन नागरिक विद्रोह है जो जल्द थमने वाला नहीं है। रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन, शिक्षा के अवसरों की कमी, रोजगार न होने जैसी चीजों ने इस आंदोलन को तेज गति से भड़कने में मदद दी है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा ने अमर उजाला से कहा पीओजेके एक गंभीर राजनीतिक-नागरिक संकट की ओर बढ़ रहा है। बुनियादी चीजों से आगे बढ़ कर अब यह आंदोलन संरचनात्मक सुधार की मांग तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, यह आंदोलन आसानी से नहीं रुकेगा। यह नागरिक विद्रोह है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। आगा ने कहा यह इलाका बहुत ज्यादा पिछड़ा है। ढंग के स्कूल-कॉलेज नहीं खुले। बिजली बनती है तो चीन चली जाती है, स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिलता। लोग लंबे समय से आधारभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

आर्थिक संकट से सबसे प्रभावित है पीओजेके
दरअसल, पाकिस्तान में जारी

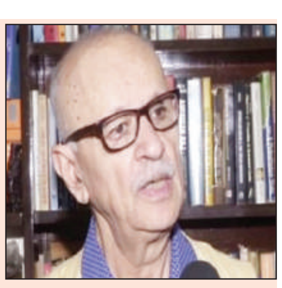

आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर पीओजेके पर पड़ा है। खाद्य सामग्री, ईंधन और बिजली जैसी मूलभूत जरूरतों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। जिससे आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में पीओजेके के नागरिकों को दोयम दर्ज का माना जाता है। यहां बिजली का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, मगर स्थानीय लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। यह ऐसा मुद्दा है जिसने जनता के गुस्से को भड़काया है। जनता में भावना है कि पाकिस्तानी सरकार पीओके के संसाधनों का शोषण कर रही है। कमर आगा कहते हैं पीओजेके का एक बड़ा वर्ग भारत से जुड़ना चाहता है। वहीं, भूराजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ कैप्टन आलोक बंसल ने कहा कि मुजफ्फराबाद में आम लोग पाकिस्तानी सेना की प्रशासनिक मामलों में दखलअंदाजी के खिलाफ आवाजें उठाने लगे हैं।

ईएमआई नहीं चुकाई तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे

आरबीआई नया सिस्टम लाने की तैयारी में

मोबाइल में पहले से एप इंस्टॉल होगा, जो उसे बंद करेगा

मुंबई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कंज्यूमर अगर एटक नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से बंद की जा सकेंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा की है। फाइनेंस एक्सपर्ट आदिल शेट्टी बताते हैं कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर भी गौर करने की जरूरत होगी। फोन, लैपटॉप या इस तरह की अन्य चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला कर्ज

कोलेटरल-फ्री होता है। यानी इनके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती। इसलिए इनकी ब्याज दर ज्यादा यानी 14-16% होती है। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो ये कर्ज सुरक्षित लोन (जैसे होम, ऑटो लोन) की कैटेगरी में आ आएंगे। ऐसे में बैंकों को ये अधिकार देने से पहले ऐसे लोन की कैटेगरी बदलनी होगी और ब्याज दरें भी घटानी होंगी।

यहां कैसे लागू किया जाएगा? आरबीआई जिस व्यवस्था पर विचार कर रहा है, वह मुख्य रूप से छोटे उपभोक्ता लोन (जैसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स) पर लागू होगी। एटक पर खरीदे प्रोडक्ट में पहले से एप या सॉफ्टवेयर डालेंगे। ग्राहक किस्त नहीं चुकाता, तो उस सॉफ्टवेयर से वह प्रोडक्ट दूर से ही लॉक कर दिया जाएगा।

2. क्या निजी डेटा को खतरा है? नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक की पूर्व सहमति ली जाए और फोन लॉक होने पर भी उसका निजी डेटा सुरक्षित रहे। यानी यहां 'सेवाएं बंद' करने का मतलब है कि फोन (या डिवाइस) इस्तेमाल योग्य न रहे, जब तक बकाया चुकता न हो। यदि इन्हें लॉक करने की अनुमति बैंकों को दे दी जाती है तो उन्हें लाखों लोगों के डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। ये डेटा वहां से लीक हो सकते हैं।

राहुल गांधी ने अमेरिका में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा

राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं, राहुल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया

नई दिल्ली
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां वे 4 देशों में जाकर राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और बिजनेस जगत के लोगों से मिलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस संबंध में जानकारी दी। पवन खेड़ा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे चार देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापार जगत के लोगों से मिलेंगे।'

ओवरसीज कांग्रेसियों ने किया स्वागत
राहुल गांधी इसके पहले अप्रैल में अमेरिका गए थे। उसके बाद से ये उनकी विदेश यात्रा की नई शुरूआत है। बोस्टन लॉगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राहुल गांधी का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने स्वागत किया। इस दौरान ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा भी वहां मौजूद रहे। बोस्टन में भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का चुनाव आयोग कॉम्प्रमाइज हो चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि इलेक्शन सिस्टम में कुछ बुनियादी खामियां हैं। राहुल ने कहा, 'महाराष्ट्र में जितने लोग हैं, उनसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया और यह सच है। चुनाव आयोग ने शाम 5:30 बजे हमें एक आंकड़ा दिया और दो घंटे बाद 7:30 बजे 65 लाख लोगों ने वोट दे दिया, जो असंभव है।' भाजपा ने इसे लेकर राहुल की आलोचना की है और उन पर राष्ट्रीय संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी सबसे ज्यादा पीएम मोदी और देश की प्रगति का अनादर करते हैं।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का चुनाव आयोग कॉम्प्रमाइज हो चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि इलेक्शन सिस्टम में कुछ बुनियादी खामियां हैं। राहुल ने कहा, 'महाराष्ट्र में जितने लोग हैं, उनसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया और यह सच है। चुनाव आयोग ने शाम 5:30 बजे हमें एक आंकड़ा दिया और दो घंटे बाद 7:30 बजे 65 लाख लोगों ने वोट दे दिया, जो असंभव है।' भाजपा ने इसे लेकर राहुल की आलोचना की है।

विदेशी धरती पर भारत का अपमान कर रहे राहुल: भाजपा

नई दिल्ली
वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए लोकतंत्र पर हमले के राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया और कहा कि वह सत्ता पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं।

राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया
उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत की प्रगति के बारे में गलत बातें कहने का भी आरोप लगाया।
प्रसाद ने कहा-राहुल गांधी विदेश में हैं। अच्छा होता अगर वह शुभकामनाएं देते। लेकिन वह भारत पर ही हमला कर रहे हैं। वह निराधार बातें करते हैं। वह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। भारत में पूर्ण लोकतंत्र है। लेकिन, राहुल गांधी की समस्या यह है कि वह सत्ता चाहते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं
कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और लोगों को बोलने की आजादी नहीं है।
राहुल गांधी सबसे ज्यादा पीएम मोदी और देश की प्रगति का अनादर करते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि अगर राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान भारत का अपमान करते रहेंगे, तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी।

राहुल की विदेश यात्रा के दौरान मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे सैम पित्रोदा

नई दिल्ली
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम ने हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि सैम पित्रोदा विदेश नीति के मामलों में राहुल गांधी का मार्गदर्शन नहीं करते, लेकिन राहुल के कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के दौरे के दौरान पित्रोदा की उनकी साथ मौजूदगी चिदंबरम के दावे को खारिज करती है।

राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा लगातार देखे जा रहे हैं
विश्लेषकों का मानना है कि पित्रोदा की उपस्थिति केवल तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित नहीं है बल्कि, यह इस विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक करीबी मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका का संकेत देती है।

पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं
राहुल गांधी वर्तमान में दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे चार देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदायों के साथ संवाद कर रहे हैं। 90 वर्षीय पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कई महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं का आयोजन किया है। इसमें अमेरिका और यूरोप की यात्राएं शामिल हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पित्रोदा के विचार कांग्रेस की व्यापक वैचारिक दिशा को दर्शाते हैं। उनका तर्क है कि पित्रोदा राहुल की विचारदृष्टि को प्रभावित करते हैं।

छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से दो और बच्चों ने तोड़ा दम, अबतक 9 की मौत

नई दिल्ली
छिंदवाड़ा जिले में बच्चों में किडनी फेलियर से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पिछले लगभग 30 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को भी इलाज के दौरान नागपुर में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 9 हो गई है। दरअसल, किडनी फेलियर से बच्चों की मौत का सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत के साथ शुरू हुआ था और एक महीने के भीतर यह 9 पर पहुंच गया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन लगातार सक्रिय हैं।

प्रतिदिन 120 बच्चों की हो रही स्क्रीनिंग
परासिया एसडीएम सौरभ कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा अब तक 1,400 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, और यह स्क्रीनिंग अभियान जारी है। वर्तमान में रोजाना 120 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि संभावित मामलों की जल्द पहचान कर उनका इलाज किया जा सके।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस बीमारी के मूल कारण का पता लगाने और प्रभावित बच्चों को उचित उपचार देने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है।

बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आए 5 किशोर, 4 की मौत

कसबा (पूर्णिया)
जवनपुर गुमटी के समीप शुक्रवार की अहले सुबह करीब 5 बजे कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर दशहरा मेला देखकर आ रहे किशोर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए,इनमें से 4 किशोरों की मौत हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार की अहले सुबह करीब 5 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 4 किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णियां में भर्ती कराया गया है। यह हादसा कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर कसबा यवनपुर रेलवे फाटक के पास हुआ। जोगबनी अररिया से दानापुर पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन से कटकर मरने वाले सभी लोग दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे।

अमृतसर पुलिस को सफलता: पूर्व कमांडो समेत तीन आतंकी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड बरामद

अमृतसर
दशहरे की रात आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे तीन आरोपियों को अमृतसर पुलिस ने बीएसएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और इन्हें सीमा पार से ड्रोन के जरिए ग्रेनेड भिजवाए गए थे। पकड़े गए इन आतंकियों में धर्मेंद्र नाम का भारतीय सेवा का एक पूर्व कमांडो भी शामिल है। जानकारी के अनुसार, खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस और

बीएसएफ की संयुक्त टीम ने अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में कार्रवाई की।
इस दौरान तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की योजना दशहरे के मौके पर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट कर दहशत फैलाने की थी, ताकि राज्य का माहौल खराब किया जा सके।

दत्तात्रेय होसबाले का संबोधन, लोगों से अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करने का किया आह्वान

नई दिल्ली
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे अपना जीवन समाज एवं राष्ट्र के लिए समर्पित करें। वह स्वयंसेवकों के पथ संचलन से पूर्व सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत करवट ले रहा है। विश्व में भारत का सम्मानजनक स्थान है, लेकिन यह यात्रा अभी और आगे तक जानी है, रुकनी नहीं चाहिए।

हमने बहुत सारे लोगों की घर वापसी कराई है: होसबाले
होसबाले ने कहा कि यहां की संस्कृति-सभ्यता का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। जो किसी दबाव में या बलपूर्वक हिन्दू धर्म के बाहर चले गए और अन्य मतावलंबी बन गए, ऐसे लोगों को वापस लाने का काम संघ कर रहा है। कुछ लोग कहते थे कि यह वापसी संभव नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों की घर वापसी (च्हदू धर्म में परावर्तन) कराई है।

संघ नहीं होता तो क्या होता: होसबाले
सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यह समाज के सहयोग से हुआ है। हम यह नहीं कहते कि संघ ने किया है, लेकिन संघ नहीं होता, तो क्या होता? संघ अपने समाज की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का काम करेगा। यह कुंडलिनी शक्ति भारत को सिरमौर बनने के लिए आवश्यक है।

मणिपुर: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित कुकी संगठन का चीफ और तीन उग्रवादी काबू

नई दिल्ली
मणिपुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां पर सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रतिबंधित कुकी संगठन के एक स्वयंभू प्रमुख समेत चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। दरअसल, सुरक्षा बलों ने चुड़चांपुर जिले के एस मुनुआम से चिन कुकी मिजो आर्मी के स्वयंभू कमांडर इन चीफ पाओखोलेन गुइटे को कस्टडी में लिया है। इन गतिविधियों में शामिल था गुइटे जानकारी के अनुसार, भारत-म्यांमार सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में गुइटे शामिल था। सुरक्षा बलों ने उसके पास से दो एके-47 राइफल, विभिन्न प्रकार के गोलाबारुद के 181 राउंड, 1,00,000 रुपये नगद और एक कार बरामद की है।

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दो कार्यकर्ता भी गिरफ्तार
इसके अलावा सुरक्षा बलों ने गुरुवार को इंफाल पश्चिम जिले में अलग-अलग जगहों से प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। वे घाटी क्षेत्र में ईंट भट्ठों के मालिकों और जनता से जबरन वसूली में शामिल थे।
वहीं, पुलिस ने बुधवार को थौबल जिले के याइरीपोक स्थित उसके आवास से संगठन के एक अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार किया। वह खदान मजदूरों से जबरन वसूली और धन उगाही में शामिल था। गौरतलब है कि पीएलए के सदस्यों ने सितंबर में बिष्णुपुर जिले के नांबोल सबल लेइकाई में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में दो जवान बलिदान हुए थे।

राजस्थान में खांसी की दवा पीने से एक और बच्चे की मौत

जयपुर
राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में वितरित की जाने वाली खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथारपन हाइड्रोबोमाइड पीने से भरतपुर में दो साल के एक और बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले सीकर जिले में पांच वर्षीय बच्चे की मौत हुई थी। वहीं बांसवाड़ा, सीकर एवं भरतपुर जिलों में 12 बच्चे बीमार हो गए थे। भरतपुर में एक प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक सहित तीन चिकित्साकर्मी भी यह दवा पीने से बीमार हो गए थे। बुधवार को सरकार ने इस दवा के वितरण पर रोक लगा दी है। दवा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार जिस केयसंस कंपनी द्वारा दवा का निर्माण एवं राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन में आपूर्ति होती थी उसके 40 सैंपल दो साल में फेल हुए हैं। इनमें खांसी, सर्दी, जुकाम आदि की दवा शामिल है। इनके सैंपल दस जिलों से लिए गए थे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार दवा पर रोक नहीं लगा रही थी।

वृद्धजन की नि:स्वार्थ सेवा और सम्मान के लिए सभी हों संकल्पित: मोहन

भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजन की निःस्वार्थ सेवा और सम्मान के लिए सभी प्रदेशवासियों से संकल्पित होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवतुल्य वृद्धजन को नमन करते हुए कहा कि वृद्धजन किसी भी संस्कृति, राष्ट्र, समाज और परिवार के सशक्त आधार होते हैं, उनके विराट अनुभव, ज्ञान और संस्कार से युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा लेते रहना चाहिए। 15 लाख 75 हजार वृद्धजन को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही है पेंशन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार वृद्धजन के मान-सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से राज्य के 15 लाख 75 हजार से अधिक वृद्धजन नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

बाढ़ पीड़ितों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठाएगी शिवसेना: शिंदे

मुंबई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में भारी वर्षा से तबाह हो गए किसानों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उनका संगठन उठाएगा। उन्होंने अपने शिवसैनिकों को इस काम में जुट जाने के निर्देश भी दिए। शिंदे ने यह घोषणा भी की कि वर्ष 2026 में शुरू होने जा रहा बालासाहेब ठाकरे का शताब्दी वर्ष शिवसेना जोरशोर से मनाएगी।

शिवसैनिक किसानों के घर-घर जाकर उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं- शिंदे
एकनाथ शिंदे मुंबई के नेस्को सेंटर में शिवसेना की परंपरागत रैली को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अपने विरोधी एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की ओर से खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि

महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात बनने के बाद से ही वह स्वयं एवं उनके शिवसैनिक किसानों के घर-घर जाकर उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित किसान परिवारों को उनके संगठन की ओर से 26 प्रकार की जीवनावश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। वह किसानों को पूरी मदद पहुंचाएंगे, और उनकी दीवाली काली नहीं होने दी जाएगी।

बाढ़ पीड़ितों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी हमारी- शिंदे
एकनाथ शिंदे ने इसी कड़ी में बाढ़ पीड़ितों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा करते हुए कहा कि वह शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे द्वारा दिए गए 80 प्रतिशत समाजसेवा एवं 20 प्रतिशत राजनीति के मूलमंत्र का पालन करते हुए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर यह कहते हुए प्रहार किया कि उन्होंने तो आजतक किसी को बिस्कुट का एक पैकेट भी नहीं भिजवाया है।

उद्धव ठाकरे ने भी रैली को संबोधित किया
बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना (यूबीटी) की भी दशहरा रैली हुई। इसे संबोधित करते हुए इसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को राज्य में आई बाढ़ के बाद पैसा मांगने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में डाले गए दस-दस हजार रुपयों पर यह कहते हुए टिप्पणी की कि अब पगार देकर मतदाता बनाए जा रहे हैं। लेकिन किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। एकनाथ शिंदे ने इसका भी उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की तुलना में पांच गुना अधिक राशि महाराष्ट्र को दी है। जिससे महाराष्ट्र में विकास के कई कार्य संपन्न हो रहे हैं।

मौसम: जम्मू-कश्मीर समेत 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, अगले कुछ दिन तक निजात नहीं

नई दिल्ली
मानसून सीजन खत्म होने के बावजूद देश के कई राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को बारिश और बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के 28 जिलों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं, बिहार के बक्सर और नवादा जिले में भी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 7 अक्तूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। झारखंड के दुमका जिले में बुधवार रात तेज बारिश के बीच 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गिलानपाड़ा मोहल्ले की सावित्री देवी घर से बाहर निकलीं और पानी भरे रास्ते पर चलते हुए नाले में गिर पड़ीं। वह नाले की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकीं और पानी के तेज बहाव में बह गईं। बाद में उनका शव मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में तेज हवा, घने बादल और तेज बारिश की संभावना जताई है। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाकों, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

यह हमें आत्मचेतना, एकाग्रता और संतुलन सिखाता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता और शांति के साथ किया जा सकता है: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

योग हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है: रेखा गुप्ता

योग हमें मी टू वी यानी मैं से हम की ओर ले जाने वाली साधना है

नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा," योग केवल व्यायाम या गतिविधि नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर हमें अनुशासित, संयमित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। मुख्यमंत्री ने यह विचार छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस समारोह एवं योग दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय योग संस्थान बीते 59 वर्षों से सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को साकार करते हुए देश और विदेश में 4,500 से अधिक निशुल्क योग साधना केंद्रों का संचालन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, "योग के माध्यम से हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और भावनात्मक रूप से स्थिर बनते हैं। यह हमें आत्मचेतना, एकाग्रता और संतुलन सिखाता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता और शांति के साथ किया जा सकता है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से उत्पन्न योग आज वैश्विक जीवन-शैली का हिस्सा बन चुका है।" योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्ति किया और कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण ने भारतीय संस्कृति के अमूल्य उपहार योग को विश्व-पटल पर प्रतिष्ठित किया है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई, जो भारत की प्राचीन परंपरा को आधुनिक जीवन का आधार बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। मुख्यमंत्री ने कहा, " बीते 11 वर्षों में योग ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति का प्रतीक बनकर करोड़ों लोगों के जीवन को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से योग आज सीमाओं से परे एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है, जिसने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को साकार किया है।"

दिल्ली सरकार को मिलेगा 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत

दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग को पर्यावरण शुल्क के नाम पर प्रतिवर्ष करीब 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अभी तक प्रतिवर्ष करीब 120 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है। इसके अलावा इस आदेश से एमसीडी को भी बड़ी राहत मिलेगी। उसे अब सामान लेकर आने वाले व्यवसायिक वाहनों की जांच नहीं करनी पड़ेगी और ऐसे वाहन चालकों के साथ होने वाली

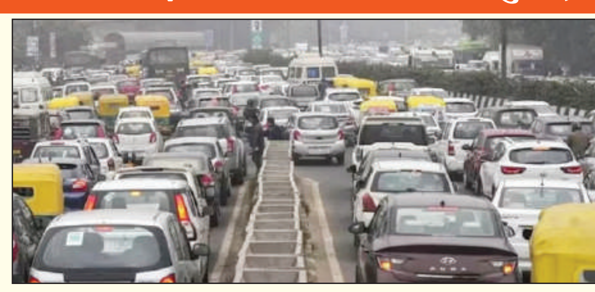

कहासुनी या विवाद की स्थिति भी खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 से लागू उस छूट को समाप्त कर दिया जिसके तहत आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले व्यावसायिक वाहन पर्यावरण शुल्क से मुक्त थे। अब सब्जी, फल, दूध, अनाज, अंडे, पोल्ट्री उत्पाद, बर्फ और नमक ले जाने वाले वाहन भी शुल्क के दायरे में आएंगे। यहां तक कि खाली या आंशिक रूप से भरे ट्रक भी शुल्क देने से नहीं बचेंगे। दरअसल, एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि छूट प्राप्त वाहनों की जांच करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बाहर से देखकर यह पहचानना असंभव है कि ट्रक में क्या सामान है। ऐसे में हर वाहन की जांच करनी पड़ती है जिससे चेक-पोस्ट पर लंबी कतारें लग जाती हैं। इस प्रक्रिया में समय की बबार्दी के साथ ट्रकों से लगातार निकलने वाला धुआं प्रदूषण को और बढ़ा देता है।

सभी पंजीकृत कश्मीरी विस्थापितों को मिलेगा राहत भत्ता

नई दिल्ली
कश्मीरी विस्थापितों की पीड़ा को समझते हुए दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और मानवीय निर्णय लिया है। सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली राहत राशि का सरलीकरण कर दिया है, जिसमें उनकी पारिवारिक आय सीमा को खत्म करना भी शामिल है। सरकार शीघ्र ही उन्हें राहत राशि देने की प्रकिया शुरू करेगी। इस निर्णय के बारे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि 1990 के दशक की शुरूआत में आतंकवाद की विभीषिका के कारण अपने घर-आंगन छोड़ने पर मजबूर हजारों कश्मीरी हिन्दू परिवार दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आ बसे। इन परिवारों को जीवनयापन के लिए सरकार की ओर से एड-हॉक मंथली रिलीफ के रूप में राहत राशि दी जाती रही है। लेकिन, समय के साथ बनी कठोर नीतियों और पुराने नियमों ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया। खासकर आय सीमा की शर्त और परिवार के रिकॉर्ड को अपडेट न कर पाने की जटिलता ने कई विस्थापित परिवारों को वर्षों तक परेशान रखा, इसका परिणाम यह निकला कि पिछले डेढ़ साल से यह राहत राशि वितरित नहीं हो पा रही थी। मुखमंत्री के अनुसार उन्होंने एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कश्मीरी विस्थापितों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं जिसके बाद राजस्व विभाग को आदेश जारी किए गए। अब इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने दो बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

राष्ट्रपति ने चार देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए

नई दिल्ली
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को मॉरिटानिया, लक्जमबर्ग, कनाडा और स्लोवेनिया के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन के अनुसार, राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने वालों में इस्लामी गणराज्य मॉरिटानिया के राजदूत अहमदौ सिदी मोहम्मद, लक्जमबर्ग के ग्रैंड डची के राजदूत क्रिश्चियन बीवर, कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर और स्लोवेनिया गणराज्य के राजदूत टोमाज मेनसिन शामिल थे।

स्पेशल सेल ने विदेश बैठे गैंगस्टरों के दो गुर्गे दबोचे, एक के पैर में लगी गोली

नई दिल्ली
दिल्ली में भी मुठभेड़ हुई है। स्पेशल सेल की टीम ने शुक्रवार सुबह कापसहेड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश राजपूत निवासी श्रीगंगानगर, राजस्थान और महिपाल निवासी भरतपुर, राजस्थान के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक, आकाश राजपूत जुलाई 2022 में असंध (करनाल) के एक अस्पताल के बाहर हुई फिरौती की गोलीबारी में शामिल था, जिसे विदेश बैठे गैंगस्टर दलेर कोटिया ने अंजाम दिलवाया था।

आकाश राजपूत पर राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था

साथ ही जुलाई 2025 में गुजरात में फिरौती के लिए हुए एक अपहरण मामले में भी वह वांछित था। इस मामले में विदेश बैठे गैंगस्टर किरितसिंह झाला ने पीड़ित से 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। आकाश राजपूत पर राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था।

जानकारी के अनुसार, आकाश राजपूत वांछित गैंगस्टरों जगदीश जागला और अभिषेक गौड़ के जरिए रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण से जुड़ चुका था। वह भारत से विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में था। इसी तरह, महिपाल भी असंध गोलीकांड में जेल गया था और बाद में बेल पर छूटने के बाद आकाश के साथ मिलकर विदेश बैठे गैंगस्टरों से जुड़ गया था। सुबह कापसहेड़ा में हुई मुठभेड़ में आकाश राजपूत को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दोनों अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।

अब दिल्ली में होगा पूरे भारत का भ्रमण, 150 कलाकारों ने किया कमाल

नई दिल्ली
अगर आप भारत भ्रमण करना चाहते हैं और देश की सांस्कृतिक विरासत और प्रमुख स्थलों को देखना चाहते हैं, तो अब आपको पूरे देश की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। आप 36 राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को एक ही जगह, यानी दिल्ली में देख सकते हैं। यह जगह है द्वारका टनल रोड। कापसहेड़ा, धौला कुआं, द्वारका और आईजीआई हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए बनाई गई लगभग चार किलोमीटर लंबी यह सुरंग, ऊंची दीवारों पर बनी चित्रकारी के माध्यम से देश की सांस्कृतिक

विरासत को देखने का मौका देती है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले भी इन कलाकृतियों की एक झलक पाने के लिए अपनी गति धीमी कर लेते हैं। 150 कलाकारों द्वारा दो साल की कड़ी मेहनत से बनाई गई इन चित्रकारियों ने दिल्ली में भारत का एक अनूठा चित्रण रचा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस द्वारका टनल रोड की दोनों ओर कुल लंबाई 8 किलोमीटर है। इस सुरंग में चित्रकारी के काम में एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष यादव का मुख्य योगदान माना जाता है। यह काम जय कुमार कंपनी के माध्यम से किया गया था। इस सुरंग की चित्रकारी दुनिया की सबसे बड़ी होने का दावा किया जाता है। एनएचएआई इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कराने के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है। सुरंग में 700 स्तंभ हैं, जो भारतीय संस्कृति को भी दर्शाते हैं।

बढ़ते स्क्रीन टाइम से किशोरों का स्वास्थ्य संकट में, कोर्स में फिजियोथेरेपी जोड़ने का आग्रह

नई दिल्ली
आधुनिक जीवनशैली में बढ़ते स्क्रीन टाइम और शारीरिक गतिविधि न करने के कारण किशोरों में मांसपेशी और हड्डी संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। पारंपरिक आदतें जैसे उकड़ू बैठना, पालथी मारकर भोजन करना या नंगे पैर चलना, जो शरीर को लचीला रखती थीं। मौजूदा समय में यह पीछे छूट गई हैं। इसके बजाय, बच्चे और किशोर घंटों झुककर मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर समय बिता रहे हैं, जबकि स्कूल में छह से सात घंटे की निरंतर बैठकी और

व्यायाम की कमी से पोस्चर विकार उत्पन्न हो रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक टीम ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सहयोग से किए गए दो वर्षीय अध्ययन में यह खुलासा किया है। अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञों ने स्कूली पाठ्यक्रम में फिजियोथेरेपी को शामिल करने की सलाह दी है, ताकि किशोरों के स्वास्थ्य को सुधारा जा सके और चोटों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। एम्स ने अक्तूबर 2023 से दिल्ली के दो निजी स्कूलों के 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 380 छात्रों पर नजर रखी गई। इस दौरान उनकी दिनचर्या, बैठने की आदतों और स्वास्थ्य पर गहन विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश किशोरों में पोस्चर संबंधी समस्याएं जैसे आगे की ओर झुकना, गर्दन और कंधों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, इलियोटिबियल बैंड की जकड़न, सपाट पैर और हैमस्ट्रिंग की कठोरता जैसी शिकायतें आम हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक गतिविधियां जैसे स्ट्रेचिंग से पहले खेलना या फर्श पर बैठना शरीर के लचीलापन को बनाए रखती हैं, लेकिन आजकल की जीवनशैली इनसे दूर कर रही है।

समस्याग्रस्त किशोरों को 12 सप्ताह की फिजियोथेरेपी दी गई, जिसके बाद अगले 24 सप्ताह तक उनकी निगरानी की गई। परिणाम में देखा गया कि बच्चों में न केवल उनकी मांसपेशी और हड्डी संबंधी दिक्कतें कम हुई, बल्कि पोस्चर में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

ट्रेड फेयर में उद्योगों में हुए बदलाव को दिखाएगा बड़ा पैवेलियन

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में बड़ा पैवेलियन बनाकर राजधानी में व्यापार को आसान बनाने के लिए किए सुधारों को प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। तैयारियों को शुरू करते हुए सरकार ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को यह जिम्मेदारी सौंपी है।

पुराना किले में कल से आयोजित होगा तीन दिवसीय 'इंद्रप्रस्थ नृत्य महोत्सव'

नई दिल्ली
दिल्ली का ऐतिहासिक पुराना किला इस बार भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की अनुगूंज से जीवंत हो उठेगा। यहां पहला इंद्रप्रस्थ नृत्य महोत्सव 5 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ दल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। तीन दिवसीय इस सांस्कृतिक पर्व में भारत के प्रख्यात कलाकारों के साथ नए कलाकार का कला का प्रदर्शन करेंगी। यह आयोजन

इतिहास, परंपरा और रचनात्मकता का अनूठा संगम होगा। इस महोत्सव में पद्म पुरस्कार से सम्मानित माधवी मुद्गल (ओडिसी) और जयराम राव (कुचिपुड़ी); संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता सुझाता मोहपात्रा (ओडिसी) और नीना प्रसाद (मोहिनीयाट्टम) अपनी प्रस्तुति देंगी। इसके साथ विश्वविख्यात नृत्यांगना सस्वती सेन की कोरियोग्राफी में कथक परंपरा, जिसमें देश के प्रमुख कथक कलाकार जैसे दीपक महाराज, गौरी दिवाकर, मोनिषा नायक, अभिमन्यु लाल, संदीप मलिक, सौविक चक्रवर्ती, शैलजा नलवड़े, अनासुआ मजूमदार, निधि प्रभु और रुद्र शंकर मिश्रा भाग लेंगे।

बाबा चैतन्यानंद की करतूत पर पर्दा डालने वाली तीन वार्डन गिरफ्तार

नई दिल्ली
दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी अल्मोड़ा के एक होटल में छात्राओं के साथ रुका था। इसकी पुष्टि बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उत्तराखंड पहुंची पुलिस टीम ने की है। टीम वहां के स्टाफ से बाबा के बारे में और पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। संस्थान में बाबा की हरकतों पर पर्दा डालने वाली और छात्राओं के विरोध को दबाने वाली तीन वार्डन को पुलिस

ने गिरफ्तार कर लिया है दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने छात्राओं के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। इस ग्रुप पर छात्राओं को योग करते हुए तस्वीर डालना अनिवार्य था। इसके पीछे उसका तर्क सेहतमंद शरीर और बेहतर दिमाग था लेकिन मंशा बेहद कुत्सित थी। योग करती हुई छात्राओं की फोटो पर अनुचित और अश्लील टिप्पणी करता था। कोई छात्रा विरोध करती उसकी आवाजा को संस्थान में कार्य करने वाली वार्डन दबा देती थीं। पुलिस को इन तस्वीरों पर चैतन्यानंद की अनुचित टिप्पणी की चैट मिल गई है। पुलिस ने आश्रम कार्यरत तीन महिलाओं श्वेता शर्मा (एसोसिएट डीन), भावना कपिल (कार्यकारी निदेशक) और काजल (वरिष्ठ संकाय) को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

महापौर ने संपत्तिकर निपटान योजना का लाभ उठाने की अपील की

नई दिल्ली
दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने शुक्रवार को जनता से संपत्ति कर माफी योजना 2025-26 संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) का लाभ उठाने की अपील की। इकबाल सिंह ने कहा कि करदाता इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से पहले के ब्याज और जुमार्ने से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, बशर्ते वे चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) और पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) तक का मूल कर बिना किसी ब्याज और जुमार्ने के अदा करें। उन्होंने बताया कि अब तक 1.29 लाख से अधिक

करदाता सुनियो योजना का लाभ उठा चुके हैं और 30 सितंबर तक 519 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति कर जमा किया जा चुका है। इनमें से लगभग 66 हजार नए करदाताओं ने पहली बार संपत्ति कर चुकाया है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। महापौर ने बताया कि चालू वर्ष 2025-26 में केवल छह महीनों में ही 11.79 लाख करदाताओं से 2270 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.9 लाख करदाताओं से लगभग 1736 करोड़ रुपये ही एकत्र हुए थे। यह आंकड़े बताते हैं कि संपत्ति कर संग्रह में 30.7 फीसदी की वृद्धि और करदाताओं की संख्या में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 2132.29 करोड़ रुपये का संपत्ति कर संग्रह हुआ था, जबकि चालू वित्त वर्ष में आधे समय में ही इससे अधिक कर जमा हो चुका है। महापौर ने जनता से अपील करते हुए कहा, ह्लयह सुनहरा अवसर है कि बिना किसी दंड और ब्याज के अपने बकाया संपत्ति कर का निपटारा करें और सुनियो योजना का पूरा लाभ उठाएं।ह्व
उल्लेखनीय है कि यह योजना 01 जून से 30 सितंबर तक के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। हालांकि एक अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच भुगतान करने वालों को मूल कर राशि पर दो फीसदी विलंब शुल्क देना होगा।

खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रयासरत: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित सुदेवा फुटबॉल क्लब में नए ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और कल्ब के पदाधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, दिल्ली में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा संकल्प है कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, अपनी प्रतिभा निखार सके और दिल्ली का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

ऊंचा करे। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ी इनामी राशि के साथ एक नई खेल नीति लागू की है। इस नई नीति के तहत अब दिल्ली में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को सात करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को पांच करोड़ और कांस्य पदक विजेता को तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह इनामी राशि देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को ग्रेड ए, बी और सी की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का अवसर भी मिलेगा।

संपादकीय

बिहार में चुनाव के आगाज के साथ दलबदल का दौर जोरो पर

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर आई है। बिहार में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद नई सूची मंगलवार को जारी होने के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 4 और 5 अक्टूबर 2025 को बिहार का दौरा करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग का यह दौरा यह संकेत देता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद राज्य में आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है।

राजनैतिक हलचल बढ़ने के साथ राज्य में पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल अपने महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक और जनता दल यूनाईटेड अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ आमने-सामने हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष के गठबंधनों के बीच होना है। इसके अलावा कई छोटे दल भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन दलों की तादाद बहुत है। प्रमुख पार्टियों समेत करीब 200 छोटे दल यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 6 ऐसे दल हैं जो पहली बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इनमें पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नवगठित राजनीतिक दल ह्य जन सुराज पार्टी ह्य भी शामिल है। इन नए दलों की चुनाव में मौजूदगी का कुछ असर चुनावी नतीजों पर नजर आ सकता है। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार के 17 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से हटा दिया, लेकिन अब 6 नए दल चुनाव मैदान में आ चुके हैं। अनुमान है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक पार्टियां चुनाव मैदान में होंगी। बिहार में रजिस्टर्ड पार्टियों की तादाद 184 है। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में छह राष्ट्रीय दल और चार राज्य स्तरीय पार्टियां थीं। राज्य का चुनाव कुल 212 राजनीतिक पार्टियों ने लड़ा था।

दलों की संख्या बढ़ने के साथ राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नेता अब रंग बदलने लगे हैं। यानी एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह परंपरा हर चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। शुरूआत बेगूसराय की राजनीति से। यहां के कद्दावर नेता और मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है।

बोगो सिंह का क्षेत्रीय प्रभाव बड़ा माना जाता है और उनके फखऊ में जाने से पार्टी को संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। बोगो सिंह ने साल 2005 में हुए दोनों विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर राजनीतिक हलचल मचाई थी।

इसके बाद वे जदयू से 2010 और 2015 में विजयी हुए। 2020 में लोजपा के राजकुमार सिंह से उन्हें नजदीकी हार मिली। लेकिन अब राजकुमार सिंह जदयू में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले बोगो सिंह राजद में शामिल हो चुके हैं। मतलब साफ है कि मटिहानी में बोगो सिंह आरजेडी से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

बोगो सिंह के अलावा भी तेजस्वी यादव के साथ भाजपा के कई पूर्व विधायकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसमें कैमूर के चैनपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बृज किशोर बिन्द और मोहनियां के पूर्व विधायक निरंजन राम हैं।

इन दोनों ने भी भाजपा को अलविदा कहकर तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी का दामन थाम लिया है।

हाल के दिनों में अन्य पार्टियों से पाला बदलने वाले नेताओं की लिस्ट देखें तो डॉ . अच्युतानंद ने 30 जून को लोजपा (रामविलास) से इस्तीफा देकर कांग्रेस जॉइन कर लिया। वह महनार से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें आशंका थी कि राम सिंह की मौजूदगी में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा।डॉ रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री, पहले जदयू, फिर भाजपा और लोजपा में रहीं। अब वे राजद के साथ हैं, जहां उन्हें उम्मीद है कि नई राजनीति में उन्हें जगह मिलेगी।रामचंद्र सदा, जो 2010 में विधायक थे, टिकट कटने के बाद लोजपा चले गए थे। अब फिर जदयू में वापस लौट आए हैं।विनोद कुमार सिंह, जदयू एमएलसी रह चुके नेता, अब कांग्रेस के टिकट पर फुलपरास से चुनाव लड़ना चाहते हैं।डॉ अशोक राम, कांग्रेस से छह बार विधायक और पूर्व मंत्री, अब जदयू में। हालांकि वह जिस सीट (कुशेश्वरस्थान) से लड़ना चाहते हैं, वह पहले से जदयू के कब्जे में है।डॉ रविंद्र चरण यादव, पूर्व मंत्री, 4 अगस्त को भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेताओं का दल बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें एक फर्क है जो नेता भाजपा की विचारधारा और उनकी सांस्कृतिक सोच से ताल्लुक रखते हैं, वे वहीं जाएंगे। जबकि सामाजिक न्याय और समता की विचारधारा वाले लोग राजद और महागठबंधन से जुड़ेंगे। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू अब ढलान पर है और आने वाले दिनों में उसका खात्मा तय है।तेजस्वी का यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वे लगातार इस नैरेटिव को मजबूत करने में लगे हैं कि नीतीश कुमार अब जनता के बीच भरोसे की राजनीति नहीं बचा पाएंगे।

जदयू की ओर से प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस पूरे घटनाक्रम पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी के आने या जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। चुनाव के पहले यह सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता दल यूनाइटेड का संगठन मजबूत है और जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करती है।जदयू की यह प्रतिक्रिया उस दबाव को कम करने की कोशिश लगती है, जो नेताओं के पलायन से पैदा हो रहा है।

ार सवाल यह है कि क्या वाकई नेताओं का जाना सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया है या यह अंदरूनी असंतोष का नतीजा है?

भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, जिनका पार्टी में कोई खास काम नहीं है, वही दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं। भाजपा का संगठन इतना बड़ा और मजबूत है कि कुछ नेताओं के जाने से पार्टी या चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।भाजपा की रणनीति साफ दिखती है। वह इस मुद्दे को हल्का करने की कोशिश कर रही है ताकि कार्यकताओं में कोई नकारात्मक संदेश न जाए।

कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने इस घटनाक्रम को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अभी तो शुरूआत है, आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष से कई बड़े नेता महागठबंधन में शामिल होंगे। उनका कहना है कि क्योंकि सत्ता पक्ष को साफ दिख रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, इसलिए वे धीरे-धीरे इधर का रुख करेंगे।कांग्रेस का यह बयान महागठबंधन की ओर आत्मविश्वास को दशार्ता है। साथ ही, यह जनता के बीच यह संदेश देने की भी कोशिश है कि सत्ता बदलना अब तय है।

देखा जाय तो बिहार की राजनीति में दल बदलने का सिलसिला नया नहीं है। हर चुनाव में ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जब नेता पाला बदलकर दूसरे खेमे में चले जाते हैं। इसके पीछे कई वजहें होती हैं जैसे 1. टिकट की गारंटीः जिन नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट मिलने की संभावना कम लगती है, वे विपक्षी खेमे में जाकर बेहतर मौका तलाशते हैं।2. सत्ता समीकरणः चुनाव से पहले हवा किस तरफ बह रही है, इसका आकलन हर नेता करता है।

जहां सत्ता की संभावना ज्यादा लगती है, वहां जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।3 .असंतोष और उपेक्षाः कई बार नेता अपनी पार्टी की नीतियों या नेतृत्व से असंतुष्ट होते हैं। ऐसे में वे दूसरी पार्टी में सम्मान और भूमिका तलाशते हैं।4। क्षेत्रीय समीकरणः बिहार की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। नेता अक्सर इस आधार पर दल बदलते हैं।

अब बड़ा सवाल यह है कि नेताओं के इस दलबदल के खेल से फायदा किसे होगा और नुकसान किसे।

महिलाओं पर डबल बोझ: शिक्षा विभाग में कपल केस अंक हटाना

डॉ. सत्यवान सौरभ

समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके सशक्तिकरण को लेकर आज भी अनेक चुनौतियाँ हैं। विशेषकर नौकरीपेशा महिलाओं के लिए यह चुनौती और भी गहरी है क्योंकि उन्हें घर और कार्यस्थल–दोनों स्थानों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। हरियाणा में हाल ही में शिक्षक स्थानांतरण नीति में किए गए बदलाव–जिनमें कपल केस के अंक हटाने की सिफारिश शामिल है–ने इस मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है। यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि महिलाओं के जीवन और उनके पारिवारिक संतुलन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।

हरियाणा के शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति २०१६ से विकसित होती रही है। इस नीति के तहत यदि एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों शिक्षक हों, तो उन्हें कपल केस अंक (प्राथमिकता अंक) दिए जाते थे। इसका उद्देश्य था कि दोनों पति-पत्नी एक ही जिले या नजदीकी स्थान पर पदस्थापित हो सकें, ताकि पारिवारिक संतुलन बना रहे और महिलाओं को नौकरी के साथ परिवार संभालने में सुविधा मिले। इस प्रकार की प्राथमिकता न केवल महिलाओं के लिए लाभकारी थी, बल्कि यह पूरे परिवार के जीवन, बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण थी।

२०१६ के बाद इस नीति में कुछ मामूली बदलाव हुए, लेकिन कपल केस अंक बने रहे। २०२३ के ड्राफ्ट स्थानांतरण नीति में अब इन अंक को हटाने की सिफारिश की गई है। इसका अर्थ है कि पति-पत्नी दोनों शिक्षक होने पर अब उन्हें पहले जैसी प्राथमिकता नहीं मिलेगी। इस बदलाव का प्रभाव सीधे महिला शिक्षिकाओं पर पड़ता है। उन्हें अब परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि पति-पत्नी अलग-अलग स्थानों पर नियुक्त हो सकते हैं। शिक्षक समुदाय में असंतोष और विरोध बढ़ सकता है।

शिक्षक संघों और सामाजिक संगठनों ने इसे पारिवारिक और लैंगिक दृष्टिकोण से आलोचना की है। उनका कहना है कि यह निर्णय महिलाओं के हितों के विरुद्ध और परिवार विरोधी कदम है।

डबल बर्डन एक सामाजिक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि महिला को घर और नौकरी–दोनों जगह अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, जबकि पुरुष केवल अपनी नौकरी पर ध्यान देते हैं। यह असमानता आज भी भारतीय समाज में गहराई से मौजूद है।

एक उदाहरण देखें। एक नौकरीपेशा पुरुष के लिए घर से भोजन ले जाना सामान्य बात है, और उसके घर के अन्य कामों का बोझ कम

होता है। वहीं नौकरीपेशा महिला को घर का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सहायता, घर की सफाई–सभी जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी नौकरी भी निभानी पड़ती है। इस असमानता के कारण महिला पर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। जब स्थानांतरण नीति जैसी सरकारी नीतियाँ भी इस असमानता को नजरअंदाज करती हैं, तो यह सशक्तिकरण के दावों को कमजोर कर देती है।

महिला सशक्तिकरण केवल नौकरी या योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका असली अर्थ है कि महिलाओं को समान अवसर, समान वेतन, समान जिम्मेदारी और सुरक्षित वातावरण मिले।

हालांकि, जब कपल केस अंक हटाए जाते हैं, तो यह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महिलाओं के लिए असमानता को बढ़ाता है। भारतीय समाज में अक्सर महिलाओं से आदर्श पत्नी और आदर्श बहू बनने की अपेक्षा की जाती है। इसका अर्थ है कि घर और परिवार की जिम्मेदारी महिला पर ही डाली जाती है, जबकि पुरुषों को इस दबाव से अपेक्षाकृत कम गुजरना पड़ता है।

कपल केस अंक हटने का असर इस असमानता को और बढ़ा देता है। महिला शिक्षिका को नौकरी में सफलता पाने के लिए अपने परिवार के समय और जिम्मेदारियों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक संतुलन बिगड़ता है, और इससे महिला की मानसिक और भावनात्मक स्थिति प्रभावित होती है। यह बदलाव महिलाओं को केवल कर्तव्यपूर्ण भूमिका तक सीमित करने जैसा है, जबकि उन्हें समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए।

समाज में सुधार की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। घर के काम को बराबरी से बाँटना चाहिए। पुरुषों को घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल में बराबरी का योगदान देना चाहिए। सरकारी नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता लाना आवश्यक है। महिलाओं को केवल त्याग और कर्तव्य का बोझ न देना, बल्कि समान अधिकार और दर्जा देना चाहिए।

नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता लाना जरूरी है। स्थानांतरण नीतियों में कपल केस जैसी प्राथमिकताओं को बनाए रखना चाहिए और महिला शिक्षिकाओं के लिए पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक संघों और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। संघों के माध्यम से सरकारी निर्णयों पर विचार-विमर्श और विरोध किया जा सकता है। मीडिया और सामाजिक मंचों पर लैंगिक असमानता और डबल बर्डन के प्रभाव पर जागरूकता फैलाना आवश्यक है।घर और नौकरी का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। परिवार में जिम्मेदारियों का बराबर बंटवारा किया जाना चाहिए। पुरुषों को घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल में बराबरी का योगदान देना चाहिए। आरटीआई और पारदर्शिता के माध्यम से शिक्षा विभाग से जानकारी लेना चाहिए कि कपल केस अंक हटाने का निर्णय क्यों और किस आधार पर लिया गया। इससे नीति बनाने में पारदर्शिता और न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित होंगे।हरियाणा में शिक्षक स्थानांतरण नीति में कपल केस अंक हटाना केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए एक चुनौती भी है। यह बदलाव महिलाओं के ऊपर डबल बर्डन को और बढ़ा देता है। महिला सशक्तिकरण का असली अर्थ केवल नौकरी या योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समान जिम्मेदारी, पारिवारिक संतुलन और सुरक्षित वातावरण भी है।

यदि समाज और सरकार सच में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो उन्हें नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता, पारिवारिक जिम्मेदारी का बराबर बंटवारा, और महिला अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना होगा। समान अवसर, समान जिम्मेदारी और पारदर्शिता ही महिलाओं के लिए वास्तविक सशक्तिकरण का आधार है। बिना इसके, किसी भी नीतिगत या आर्थिक पहल का प्रभाव सीमित रहेगा और डबल बर्डन जैसी समस्याएं बनी रहेंगी।

रोजगार का भविष्य: इंसान बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

सुनील कुमार महला

आज विज्ञान और तकनीक का युग है।विज्ञान और तकनीक के इस युग ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है और एआइ भी निश्चित रूप से इनमें से एक है। कहना गलत नहीं होगा कि आज हम सभी एआइ(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जमाने में सांस ले रहे हैं और वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तेजी से हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। एआइ से काम करना आज बहुत आसान या यूं कहें कि सरल हो गया है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, कृषि, उधोग व व्यापार, परिवहन, सुरक्षा, बैंकिंग व वित्त, मनोरंजन, घर और दैनिक जीवन, अंतरिक्ष तक आज कौनसा क्षेत्र है, जहां एआइ से काम नहीं हो रहा है ? यानी कि सब जगह आज एआइ का धड़ल्ले से इस्तेमाल या प्रयोग किया जा रहा है।शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बैंकिंग, कृषि, उद्योग और सुरक्षा जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में एआई का प्रयोग बढ़ने से जहां अनेक नए अवसर पैदा हो रहे हैं, वहीं रोजगार के परिदृश्य में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित करेगी और काम करने के तरीकों में मूलभूत परिवर्तन लाएगी।पाठक जानते हैं कि मानव की तुलना में एआई विभिन्न कार्यों को तेजी और सटीकता से करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, आज के समय बैंकिंग सेक्टर में डाटा एंट्री, ग्राहक सेवा(कस्टमर सर्विस) या लेन-देन संबंधी प्रक्रियाओं को चैटबॉट और ऑटोमेशन द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार, फैक्टरियों में मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल, उत्पादन प्रक्रिया को तेज और त्रुटिरहित बनाने के लिए हो रहा है। परिणामस्वरूप, कई जगह मानव श्रमिकों(मैनपावर) की आवश्यकता घटने लगी है। बहरहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि एआई का प्रभाव मुख्यतः उन क्षेत्रों पर अधिक होगा, जहां कार्य दोहराए जाते हैं और निर्णय सीमित जानकारी के आधार पर लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर सपोर्ट के लिए पहले जहां कॉल सेंटर में हजारों कर्मचारी कार्य करते थे, आज वहां चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट यह काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कस्टमर सपोर्ट तो एआइ के कारण पूरी तरह से खत्म हो सकती है।इसी प्रकार से निर्माण उद्योग की बात करें तो वहां उत्पादन, पैकेजिंग और क्वालिटी चेक जैसे कार्य रोबोट द्वारा किए जा रहे हैं।

आज डिलीवरी ड्रोन से काम हो रहा है, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां आ चुकीं हैं, ये सब एआइ के कारण संभव

हुआ है, यह ठीक है लेकिन भविष्य में ये सब परिवहन के क्षेत्र में ड्राइवरों और डिलीवरी कर्मचारियों की मांग कम कर सकते हैं। आज एआइ के कारण लेखा-जोखा और बैंकिंग का काम आसान हो गया है। एआई आधारित सॉफ्टवेयर तुरंत गणना, विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, पहले इसके लिए मैनपावर की जरूरत होती थी। आज एआइ का उपयोग मीडिया के क्षेत्र में और कंटेंट तैयार करने में किया जा रहा है। समाचार लेखन, अनुवाद और वीडियो संपादन जैसे काम भी अब आंशिक रूप से एआई कर रहा है, ऐसे में मैनपावर की जरूरत पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। लेकिन यहां यह भी एक तथ्य है कि हालांकि, एआई से नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन साथ ही नए रोजगार भी बनेंगे। उदाहरण के लिए, एआई सिस्टम को डिजाइन करने, उसका रखरखाव करने और उसे सुरक्षित बनाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। आज के युग में निरंतर डाटा वैज्ञानिक, मशीन लर्निंग इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ और एआई नैतिकता से जुड़े पदों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, यह भी एक तथ्य है कि एआई के कारण हेल्थकेयर, शिक्षा और कृषि क्षेत्र समेत अनेक क्षेत्रों में में नए नवाचार होंगे, जिससे नई तरह की नौकरियां पैदा होंगी। संक्षेप में कहें तो एआइ के दोनों पहलू हैं। इसमें अवसर (अपार्चुनिटीज) भी हैं और चुनौतियाँ (चैलेंजेज) भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर लोगों को नए कौशल सिखाना और तकनीक के अनुकूल बनाना आज के समय की बड़ी मांग है।इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, एआई का नैतिक और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना भी जरूरी है ताकि यह केवल मुनाफे का साधन न रहकर मानव कल्याण का साधन बने। पाठकों को बताता चलूं कि एआई मशीन आधारित तकनीक है, इसमें मानव जैसी भावनाएँ, संवेदनाएँ या नैतिक मूल्य स्वयं से मौजूद नहीं होते। यह केवल डेटा, एल्गोरिद्म और प्रोग्रामिंग पर आधारित होकर कार्य करता है। इसलिए इसका नैतिक और जिम्मेदार उपयोग पूरी तरह से मानव पर निर्भर है और एआइ जिम्मेदार और नैतिक उपयोग तभी संभव है जब इंसान इसे नियंत्रित, नियोजित और पारदर्शी तरीके से अपनाए। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि ओपनएआइ के सीईओ सैम ऑल्टमैन और वालमार्ट के सीईओ डग मैक्मिलन ने हाल ही में खुलकर यह बात कही है कि एआइ से काम करने के तरीके बदलेंगे और बहुत सारी नौकरियां प्रभावित होंगी। सैम ऑल्टमैन ने यह चेतावनी दी है कि एआइ के विकास से लगभग 30-40 % कार्य (टास्क) मानवों द्वारा आज की तरह किए जाने वाले काम होंगे, एआइ उन्हें करने लगेगा। उन्होंने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि पूरी नौकरियाँ खत्म हों, बल्कि ह्यटास्कह्न का हिस्सा बदलेगा।वास्तव में कुछ कामों में मानवता की भूमिका जैसे कि दूसरों की देखभाल करना, दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील होना और ऐसे कौशल, जिन्हें मशीनें पूरी तरह से न दोहरा सकेंगी, भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण होंगी।आल्टमेन का यह मानना है कि एआइ सिस्टम उम्मीद से कहीं तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले वर्षों में आगे निकलकर सुपरइंटेलिजेंस के स्तर तक पहुंच सकता है। वास्तव , यह ऐसी समस्याओं का हल खोज पाएगा जिनसे इंसान खुद नहीं निपट सकते हैं।

इधर,डग मैक्मिलन (वालमार्ट सीईओ) ने यह बात कही है कि ह्यप्रायः हर नौकरी बदलेगी।ह्न यानी हर कार्य में एआइ टूल्स, ऑटोमेशन और नए तरीके काम में आएँगे। वास्तव में, एआइ के कारण बदलाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के होंगे। कुछ नौकरियाँ घटेंगी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। वालमार्ट के डग मैक्मिलन ने समूह की एक कांन्फ्रेंस में चेतावनी देते हुए कहा है कि एआइ वर्क फोर्स के हर क्षेत्र को छुएगी।

यहां गौरतलब है कि वालमार्ट फिलहाल अपने 21 लाख कर्मचारियों को एआइ में प्रशिक्षित कर रहा है।

ट्रंप के कार्यकाल के पहले शटडाउन से अमेरिका में फिर ठप हो जाएंगी सरकारी सेवाएं !

अशोक भाटिया

अमेरिका एक बार फिर सरकारी गतिविधियों के ठप होने की कगार पर खड़ा है। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने अस्थायी फंडिंग विधेयक पास कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 60 मतों की जरूरत थी, जबकि केवल 55 वोट ही मिले। इससे पहले, सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने अल्पकालिक उपाय के रूप में ट्रंप प्रशासन को 21 नवंबर तक फंड उपलब्ध कराने के लिए सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पेश किया था। लेकिन देर रात तक चलने वाली बहस के बाद यह प्रस्ताव असफल हो गया। सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच जोरदार विवाद देखने को मिला। आखिरकार, 100 सदस्यीय सीनेट में इसे पास कराने के लिए आवश्यक 60 वोट नहीं जुट सके और यह प्रस्ताव 55-45 के अंतर से गिर गया।परिणामस्वरूप यह बिल विफल हो गया और अब कई संघीय विभागों की गतिविधियां ठप होने की स्थिति में हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार, बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास न होने पर ह्यगैर-जरूरीह्न सरकारी सेवाओं को रोकना अनिवार्य होता है।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुद्दों को विधेयक में शामिल किया जाए। वे इस अस्थायी फंडिंग बिल में संशोधन करना चाहते हैं ताकि लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि उन्हें इस मुद्दे से अलग से निपटना होगा।मंगलवार को अमेरिका को छह साल में पहली बार शटडाउन का सामना करना पड़ सकता है। डेमोक्रेट्स और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतभेदों ने फंडिंग बढ़ाने की आखिरी कोशिश को नाकाम कर दिया। सीनेटरों की यह कोशिश विफल रही कि फंडिंग जारी रहे और सरकार सामान्य रूप से काम करती रहे।

ज्ञात हो कि सरकारी शटडाउन तब होता है, जब कांग्रेस संघीय एजेंसियों को चलाने के लिए वार्षिक व्यय विधेयकों पर सहमत नहीं हो पाती। एंटीडेफिशिएंसी एक्ट एजेंसियों को बिना अनुमति के पैसा खर्च करने से रोकता है, इसलिए जब पैसा खत्म हो जाता है, तो सरकार का ज्यादातर काम भी बंद हो जाता है।अमेरिकी सरकार के अलग-अलग विभागों को चलाने

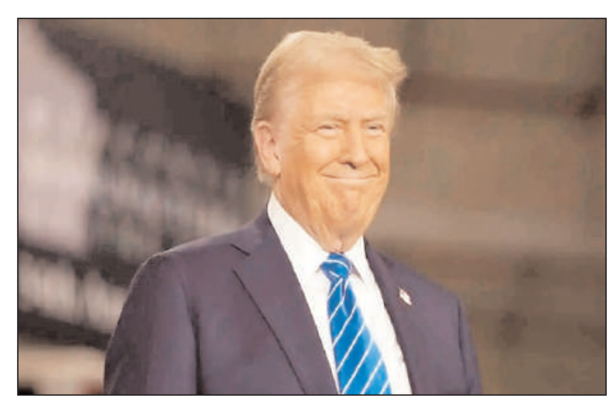

के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है। इसके लिए संसद (कांग्रेस) से बजट या फंडिंग बिल पारित कराना जरूरी होता है। लेकिन जब राजनीतिक मतभेद या गतिरोध की वजह से तय समयसीमा में फंडिंग बिल पारित नहीं हो पाता, तो सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च करने के लिए फंड नहीं बचता। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर-जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं, जिसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है। यह आमतौर पर अस्थायी होता है, लेकिन इस बार ट्रंप कई विभागों को स्थायी रूप से बंद करने और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी में हैं।अगर समय सीमा बीत जाती है तो एजेंसियों को ह्यगैर-अपवादितह्न कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना शुरू करना होगा। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो जीवन या संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित नहीं हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिनों के बंद के दौरान, 340,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों ने सरकार के फिर से खुलने तक बिना वेतन के काम किया।इस बार, एफबीआई जांच, सीआईए ऑपरेशन, हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा जांच, मेडिकेयर दावे और पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्य जारी रहेंगे। डाक वितरण भी अप्रभावित रहेगा क्योंकि अमेरिकी डाक सेवा अपने स्वयं के राजस्व पर चलती है।

लेकिन कई एजेंसियां अपने काम में भारी कटौती करेंगी। शिक्षा विभाग अपने करीब 90% कर्मचारियों की छंटनी करेगा, हालांकि छात्र सहायता जारी रहेगी। स्मिथसोनियन संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर अपने दरवाजे बंद कर देंगे। FDA ने दवा और उपकरणों की मंजूरी में देरी की चेतावनी दी है। और राष्ट्रीय उद्यान सेवा कुछ स्थलों के दरवाजे बंद कर देगी, जबकि अन्य सीमित कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे।

सरकारी शटडाउन तब होता है, जब कांग्रेस संघीय एजेंसियों को चलाने के लिए वार्षिक व्यय विधेयकों पर सहमत नहीं हो पाती। एंटीडेफिशिएंसी एक्ट एजेंसियों को बिना अनुमति के पैसा खर्च करने से रोकता है, इसलिए जब पैसा खत्म हो जाता है, तो सरकार का ज्यादातर काम भी बंद हो जाता है।अमेरिकी सरकार के अलग-अलग विभागों को चलाने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है। इसके लिए संसद (कांग्रेस) से बजट या फंडिंग बिल पारित कराना जरूरी होता है। लेकिन जब राजनीतिक मतभेद या गतिरोध की वजह से तय समयसीमा में फंडिंग बिल पारित नहीं हो पाता, तो सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च करने के लिए फंड नहीं बचता। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर-जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं, जिसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है। यह आमतौर पर अस्थायी होता है, लेकिन इस बार ट्रंप कई विभागों को स्थायी रूप से बंद करने और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी में हैं।

अगर समय सीमा बीत जाती है तो एजेंसियों को ह्यगैर-अपवादितह्न कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना शुरू करना होगा। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो जीवन या संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित नहीं हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिनों के बंद के दौरान, 340,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों ने सरकार के फिर से खुलने तक बिना वेतन के काम किया।इस बार, एफबीआई जांच, सीआईए ऑपरेशन, हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा जांच, मेडिकेयर दावे और पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्य जारी रहेंगे। डाक वितरण भी अप्रभावित रहेगा क्योंकि अमेरिकी डाक सेवा अपने स्वयं के राजस्व पर चलती है।

पुतिन का चेतावनी भरा बयान, 'यूरोप ने उकसाया तो तुरंत देंगे जवाब'

एजेंसी

सोची (रूस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को चेतावनी दी कि यदि यूरोप ने रूस को उकसाया तो जवाब तुरंत मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप में सैन्यीकरण हिस्टीरिया से प्रेरित है, लेकिन रूस की अमेरिका-नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन पर हमला करने की कोई मंशा नहीं है। ब्लैक सी रिसॉर्ट शहर सोची में वल्दाई डिस्कशन ग्रुप को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा- अगर किसी को अब भी हमारे साथ सैन्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा है, तो कर ले। रूस की प्रतिक्रिया देर से नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि रूस ने सदियों से साबित किया है कि उकसाए जाने पर वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है। इस दौरान उन्होंने जर्मनी की उस महत्वाकांक्षा का भी उल्लेख किया, जिसमें वह यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। पुतिन ने यूरोप के नेताओं पर हिस्टीरिया फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, वे बार-बार यह मंत्र दोहराते हैं कि रूसियों से युद्ध दरवाजे पर है। यह सब बकवास है। साथ ही, पुतिन ने इस संभावना को खारिज किया कि रूस कभी नाटो सदस्य देशों पर हमला करेगा। उन्होंने कहा, सच में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, शांत रहो, चैन से सोओ और अपनी समस्याओं पर ध्यान दो। बस यूरोपियन शहरों की सड़कों पर जो हो रहा है, उसे देखो।

जेलेंस्की और डेनमार्क की फ्रेडरिकसेन का संदेश- 'यूरोप को रूस से रिश्ते तोड़कर सशक्त बनाना होगा'

कीव/ब्रसेल्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने यूरोपीय देशों से एकजुट होकर रूस के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस लगातार 'विनाशकारी कदम' बढ़ा रहा है और यूरोप की सुरक्षा के लिए अब राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाना जरूरी है, रूस से रिश्ते तोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, 'सच्ची सुरक्षा केवल संयुक्त कार्रवाई और एकजुट प्रयासों से सुनिश्चित हो सकती है। किसी को इस खतरे के सामने अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।जेलेंस्की ने हंगरी और स्लोवाकिया जैसी देशों पर दबाव डाला कि वे रूस से ऊर्जा आयात बंद करें। उनका कहना था, रूस के साथ किसी भी प्रकार का संबंध आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने कम संबंध होंगे, जीवन उतना ही सुरक्षित होगा।डेनमार्क की फ्रेडरिकसेन ने भी यूरोपीय नेताओं को चेताया कि रूस यूरोप के लिए बढ़ता खतरा है। उन्होंने कहा, हाल ही में हमने देखा है कि रूस ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन, हाइब्रिड हमले, सीमाओं पर प्रवासियों को धकेलना, चुनावों में दखल और साइबर हमले बढ़ा दिए हैं। रूस हमें आज पहले से कहीं अधिक परख रहा है। हमें एकजुट और मजबूत खड़ा होना होगा।

रूस का कहना है- यह कोई शीत युद्ध नहीं, पश्चिम के साथ उग्र संघर्ष है

मॉस्को। रूस ने गुरुवार को कहा कि पश्चिमी देशों के साथ उसका रिश्ता अब 'शीत युद्ध' (कोल्ड वार) जैसा नहीं रहा, बल्कि यह एक 'उग्र संघष' बन चुका है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ और नाटो 'झूठे आरोप' लगाकर अपने विशाल रक्षा बजट को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जखारोवा ने कहा, 'मैं शीत युद्ध से तुलना से सहमत नहीं हूं। यहां बहुत समय से ठंड नहीं है, बल्कि आग है। हम पहले से ही संघर्ष के एक अलग रूप में हैं।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सबसे घातक लड़ाई का रूप ले लिया है और रूस तथा पश्चिमी देशों के बीच टकराव को 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे गंभीर स्तर तक पहुंचा दिया है पिछले दो महीनों में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई शिखर बैठक के बावजूद शांति की संभावना और दूर होती दिख रही है। रूसी सेनाएं यूक्रेन में आगे बढ़ रही हैं, रूस पर नाटो के हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजने के आरोप लग रहे हैं और वाशिंगटन प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप तक की बात कर रहा हैयूरोपीय देशों के आरोपों पर कि रूस ने नाटो क्षेत्र में घुसपैठ, तोड़फोड़ और साइबर हमले किए हैं, जखारोवा ने पलटवार किया कि ये बिन आधार के आरोप हैं और संकेत देते हैं कि नाटो व यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।

इथियोपिया के मिन्जर शेनकोरा की एक चर्च में मचान ढहने से 36 की मौत, 200 से अधिक घायल

अदिस अबाबा। इथियोपिया के मिन्जर शेनकोरा जिले में सुबह एक धार्मिक उत्सव के दौरान आंशिक रूप से निर्मित चर्च में बने मचान के टूटने से कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हो गए। स्थानीय पुलिस प्रमुख अहमद गेबेयेहु ने सरकारी फाना ब्रॉडकास्टिंग को बताया कि यह हादसा अम्हारा क्षेत्र के उत्तरी शेवा जोन के अरटी सेंट मैरी चर्च में हुआजहां तीर्थयात्री वार्षिक वर्जिन मैरी उत्सव के लिए एकत्र हुए थे। यह मचान भीड़ के भार को सहन न कर सकने के कारण अचानक टूट गया। इस बीच एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब पौने आठ बजे मचान अचानक से टूट गया जिससे दर्जनों लोग मचान की भारी लकड़ी और धातुओं के खंभों के नीचे दब गए। बचाव कार्य जारी है लेकिन कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। घायलों को राजधानी अदीस अबाबा के अस्पतालों में ले जाया गया है जहां कईयों की हालत नाजुक है।

पुतिन का बयानः अमेरिकी दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा, मोदी देश की संप्रभुता के खिलाफ फैसला कभी नहीं करेंगे

एजेंसी

सोची (रूस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। वाल्दाई पॉलिसी फोरम में गुरुवार को संबोधन के दौरान पुतिन ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, जिससे भारत की संप्रभुता से समझौता हो। पुतिन ने कहा कि अगर रूस से तेल खरीदने पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत अगर रूसी तेल की खरीद रोकता है, तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

रूसी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत जैसे देश में जनता अपने नेतृत्व पर पैनी नजर रखती है और भारतीय लोग कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका देश किसी भी ताकत के सामने झुके। पुतिन ने यह भी जोड़ा कि अगर रूसी तेल की आपूर्ति बंद होती है, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें प्रति बैरल 100 डॉलर से भी ऊपर जा सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत के साथ रिश्तों को 'दोस्ताना' बताते हुए पुतिन ने कहा कि वे मोदी के साथ भरोसे के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने दिसंबर की शुरुआत में होने वाली अपनी भारत यात्रा को लेकर संतोष जताया और रूसी सरकार को निर्देश दिया कि व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

पुतिन ने सुझाव दिया कि भारत चाहे तो रूस से ज्यादा कृषि उत्पाद और दवाइयां आयात करके व्यापार संतुलन को साध सकता है। अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए पुतिन ने कहा कि वाशिंगटन भारत जैसे देशों पर रूसी ऊर्जा न खरीदने का दबाव डालता है, जबकि खुद यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर रहता है।

इंडोनेशिया में इमारत हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हुई

एजेंसी

जकार्ता। इंडोनेशिया में पूर्वी जावा द्वीप में एक छात्रावास की इमारत ढह जाने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है जबकि बचावकर्मी अभी भी मलबे में फंसे छात्रों की तलाश में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बचावकर्मियों द्वारा मलबे से और शव बरामद किए के कारण अब तक नौ छात्रों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि कई लोग अब भी लापता बताए गए हैं। यह दुघर्टना सोमवार को हुई थी।इस बीच मलबे में कई छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए

बचाव दल दिन-रात काम कर रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों में से अधिकांश छात्र हैं। स्थानीय प्रशासन ने बचाव अभियान को तेज करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए हैं। इस बीच इंडोनेशियाई सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है जिसमें चिकित्सा सुविधाएं और अस्थायी आश्रय शामिल हैं।

टैरिफ को लेकर भारत-अमेरिका के बीच बनेगी बात? यूएसटीआर ने भारतीय दृष्टिकोण को बताया व्यवहारिक

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीर ने व्यापार वार्ता में भारत के दृष्टिकोण को 'व्यावहारिक' बताया और कहा कि दोनों पक्ष 'समझौते पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।' न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान, ग्रीर ने भारत के साथ जारी बातचीत के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ÷भारतीय व्यावहारिक रुख अपना रहे हैं। हम प्रशासन के पहले दिन से ही व्यापार के मोर्चे पर भारतीयों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसलिए, जब आप भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ की बात करते हैं, तो उस 25 प्रतिशत का आधा हिस्सा वास्तव में व्यापार से जुड़ा होता है। यह पारस्परिक टैरिफ है। हम इसी पर बातचीत करके समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएसटीआर ग्रीर के बीच 22 सितंबर को मुलाकात हुई। मुलाकात के कुछ दिनों बाद ग्रीर का यह बयान सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया और दोनों पक्षों को जल्द ही एक अंतरिम समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के अलग-अलग पहलुओं पर अमेरिकी सरकार के साथ 'रचनात्मक बैठकें' कीं। भारत की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया, 'दोनों पक्षों ने डील की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया गया।' ग्रीर ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी बात की और तर्क दिया कि अमेरिका किसी संप्रभु राष्ट्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत ने हमेशा इतना रूसी तेल नहीं खरीदा है। ऐसा नहीं है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई आधारभूत हिस्सा है। जाहिर है, वे एक संप्रभु देश हैं। हम दूसरे देशों पर यह थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वे किसके साथ संबंध रख सकते हैं और किसके साथ नहीं।' ग्रीर का यह भी मानना था कि नई दिल्ली यूक्रेन में संघर्ष समाप्त करने के अमेरिकी उद्देश्य को समझती है और अपनी ऊर्जा जरूरतों में बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे इसे समझते हैं। मैं देख सकता हूं कि वे बदलाव लाना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस से तेल खरीदने वाला भारत अकेला देश नहीं है, और ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय और चीनी देशों पर अपनी खरीद रोकने का दबाव डाला। यूएसटीआर ग्रीर ने जोर देकर कहा, हम अपने यूरोपीय सहयोगियों से पहले ही बात कर चुके हैं, जिनमें से कुछ आज भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, जो कि एक अजीब बात है। इसलिए, हम सिर्फ भारतीयों से ही इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने चीन से भी इस बारे में बात की।

अमेरिकी विमानों की घुसपैठ से भन्नाया वेनेजुएला, बोला-ऐसी गलती मत करो

एजेंसी

कराकस । अमेरिका ने वेनेजुएला और अन्य ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक मादक पदार्थ तस्करी विरोधी अभियान चलाते हुए दक्षिणी कैरिबियन सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं। अब एक बार फिर अमेरिकी लड़ाकू विमान वेनेजुएला के आसमान में उड़ते देखे गए। वेनेजुएला ने इसे उकसाने की कार्रवाई बताते हुए इस अवैध घुसपैठ की निंदा की है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने यह कहते हुए छोटी नावों पर हमला कर दिया था कि ये वेनेजुएला से ड्रग्स की तस्करी में शामिल थीं। इन हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने वाशिंगटन को दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पर सैन्य हमलों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा, ऐसी गलती मत करो। वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवन गिल ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हमारे तटों से लगभग 75 किलोमीटर दूर अमेरिकी विमानों के उड़ने का पता लगाया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह कदम वेनेजुएला के लिए एक उकसावे की कार्रवाई है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता के

लिए खतरा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। समाचार एजेंसी के अनुसार कैरेबियन सागर में अमेरिका के युद्धपोतों की मौजूदगी ने वेनेजुएला के नागरिक विमानों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

इससे पहले, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने दक्षिणी कैरेबियन सागर में अमेरिकी विमानों की तैनाती और वेनेजुएला के उन लोगों के खिलाफ अमेरिकी सरकार के सैन्य उत्पीड़न की निंदा की, जो शांति, काम और खुशी चाहते हैं। पैड्रिनो ने कहा कि वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली ने 35,000 फीट की ऊंचाई पर 400 समुद्री मील की गति से उड़ते हुए कम से कम पांच अमेरिकी विमानों का पता लगाया। बाद में विदेश मंत्रालय के साथ एक संयुक्त बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विदेशी विमानों की घुसपैठ वेनेजुएला के तट से 75 किलोमीटर दूर हुई। अधिकारियों के अनुसार, कोलंबिया की एवियनका एयरलाइन का एक विमान भी अमेरिकी विमानों के वेनेजुएला की सरहद में उड़ने का गवाह बना।

पाकिस्तान के मानवाधिकार समूहों ने सरकार पर मीडिया और एनजीओ के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने का लगाया आरोप

एजेंसी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान में कई मानवाधिकार संगठनों और वकालत समूहों ने देश के मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार की आलोचना की और इस हरकत को बेहद गैरजिम्मेदाराना बताया। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने कई अन्य वकालत समूहों और महिला एक्शन फोरम - लाहौर, शिरकत गाह (महिला शोध केंद्र), दक्षिण एशिया भागीदारी-पाकिस्तान, सिमोर्ग एक गैर-सरकारी नारीवादी कार्यकर्ता संगठन और कानूनी सहायता, सहायता और निपटान केंद्र (सीएलएएएस) समेत अधिकार निकायों ने पाकिस्तानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हाल के विज्ञापन की कड़ी निंदा की। दरअसल, पाकिस्तानी सरकार के इन विज्ञापनों में पत्रकारों, गैर-सरकारी संगठनों में काम करने वालों और 'फ्रीलांस' शोधकर्ताओं को यह दिखाया गया है कि वे 'दुश्मन का प्रचार' करने वाले संभावित साधन हो सकते हैं। इन

समूहों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया, 'नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र मीडिया को सूचना युद्ध का हिस्सा बताना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और उन स्वतंत्रताओं को कमजोर करता है जो एक लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखती हैं। पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकार और गैर-सरकारी संगठन पहले से ही अत्यधिक प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जिसमें लगातार उत्पीड़न, पंजीकरण और रिपोर्टिंग की कठिन जरूरतें, धन की मनमानी जांच और लगातार बढ़ता हुआ असुरक्षित माहौल शामिल है। बयान में आगे कहा गया, 'उनके काम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना उन लोगों के लिए और भी खतरनाक है जो अधिकारों की रक्षा और जनता को सूचित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसी चीजों का इस्तेमाल पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों पर निगरानी, धमकी और यहां तक कि शारीरिक हमलों को सही ठहराने के लिए किया गया है। समूहों ने इस बात पर खास जोर दिया कि नागरिकों से बिना किसी कानूनी सुरक्षा उपाय के संदिग्ध एनजीओ कार्यकर्ताओं या पत्रकारों की शिकायत करने का आग्रह करना, मनमाने ढंग से निशाना बनाए जाने, उत्पीड़न और सेंसरशिप को वैध बनाने के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अलावा, समूहों ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे डिजिटल तकनीकों को बड़े पैमाने पर फंसाने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अशांति, भय और अराजकता फैलाना है, इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम और उसके संशोधनों सहित पाकिस्तान के अन्य कानूनों द्वारा पहले से ही स्थापित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले भयावह प्रभाव को और बढ़ाना है।

हमास को ट्रंप शांति योजना मानने के लिए राजी करने में जुटा मिस्र

एजेंसी

पेरिस। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाटी ने कहा कि काहिरा, कतर और तुर्की के साथ मिलकर हमास को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने इस योजना को ठुकराया, तो संघर्ष और अधिक बढ़ जाएगा। पेरिस स्थित फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हुए अब्देलाटी ने कहा, हमें किसी भी पक्ष को यह बहाना नहीं देना चाहिए कि वे हमास को गाजा में नागरिकों की बर्बर हत्याओं का आधार बनाएं। यह सिर्फ 07 अक्टूबर की घटना तक सीमित नहीं है। अब यह बदले से आगे निकलकर जातीय सफाए और नरसंहार का रूप ले चुका है। अब बहुत हो चुका। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है, हमास को हथियार डालने होंगे और इजराइल को कोई ऐसा बहाना नहीं मिलना चाहिए जिससे वह अपना आक्रामक अभियान जारी रखे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजराइल की कार्रवाई में अब तक गाजा में 66,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इस हफ्ते की शुरुआत में 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें तत्काल युद्धविराम, हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल में कैद फिलिस्तीनियों की अदला-बदली, गाजा से चरणबद्ध इजराइली वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा संचालित एक संक्रमणकालीन सरकार का प्रावधान शामिल है। ट्रंप ने हमास को इस योजना को मानने के लिए तीन से चार दिन का समय दिया है।

कठिन और विभाजित समय में गांधी का संदेश शांति के लिए काम करने की ताकत देता है : एंटोनियो गुटेरेस

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महात्मा गांधी के संदेशों में शक्ति और प्रेरणा तलाशने का आह्वान किया है, ताकि एक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण की दिशा में काम किया जा सके। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, दुनिया भर में अलग-अलग स्थानों पर महात्मा गांधी और उनके आदर्शों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के साथ गांधी जयंती के अवसर पर अपने संदेश में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, ÷गांधीजी समझते थे कि अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं है, यह साहसी लोगों की ताकत है, जिसमें बिना घृणा के अन्याय का विरोध करने, क्रूरता के बिना उत्पीड़न का सामना करने और प्रभुत्व के बजाय सम्मान के माध्यम से शांति स्थापित करने की शक्ति है।' उन्होंने कहा कि आज की अनुसरण करने, दुखों को समाप्त करने, कूटनीति को आगे बढ़ाने, विभाजनों को दूर करने और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण, स्थायी और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की शक्ति प्राप्त

दुनिया में, 'हिंसा संवाद का स्थान ले रही है' और 'शांति की नींव दबाव में है'। इस खतरनाक और विभाजित समय में, आइए हम उनके नेतृत्व का करें। बता दें, महासभा ने 2007 में हर साल गांधी जयंती पर 'अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता' को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा दिवस की स्थापना की थी। इस मौके पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि शांति की लालसा सदियों से और विभिन्न सभ्यताओं में आह्वान और अभिवादन के माध्यम से व्यक्त की जाती रही है। यह वेदों और उपनिषदों के भारतीय शांति मंत्रों में व्यक्त होती है, जो बाहरी दुनिया और दिव्य जगत में हमारे भीतर शांति या शांति का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा, 'यह अरबी अभिवादन में अल-सलाम या शांति और यहूदी अभिवादन में शालोम या शांति की कामना में निहित है। गांधीवादी मूल्यों और स्थायी शांति के बीच गहरा संबंध आज की जटिल वैश्विक चुनौतियों के बीच भी इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए एक सशक्त आधार प्रस्तुत करता है।

बलोचिस्तान के शेरानी में 7 बलोच लड़ाके मारे गए

एजेंसी

क्वेटा। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को यहां दावा कि सुरक्षाबलों ने बलोचिस्तान के शेरानी ज़िले में एक खुफिया अभियान के दौरान सात बलोच लड़ाकों को मार गिराया । समाचारपत्र डान ने सेना की मीडिया मामलों की शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर)के हवाले से यह खबर दी। सेना के मुताबिक एक अक्तूबर को सुरक्षाबलों ने शेरानी में उग्रवादी संगठन फितना अल ख़्वारिज से जुड़े लड़ाकों की कथित मौजूदगी का पता चलने पर एक अभियान चलाया जिसमे उग्रवादियों के ठिकानों पर प्रभावी ढंग से हमला किया गया। हमले के दौरान भीषण गोलीबारी के बाद सात लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। सेना ने इस संगठन के तार भारत से जुड़े होने का आरोप लगाया और बलोचिस्तान में जारी संघर्ष को भारत प्रायोजित करार दिया। फितना अल ख़्वारिज शब्द का इस्तेमाल सरकार प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े अन्य उग्रवादियों की पहचान के लिए तलाशी अभियान जारी है। सेना ने कथित रूप से भारत प्रायोजित उग्रवाद के खतरे को खत्म करने और दोषियों

उग्रवादियों के लिए करती है। बयान के अनुसार , लड़ाकों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए । ये लोग देश विरोधी कई गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इलाके में छिपे को न्याय के कटघरे में लाने के राष्ट्र के प्रति कृतसंकल्पित होने की बात कही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है।

मैनचेस्टर में सिनेगॉग पर आतंकी हमला, फ्रांस ने जताई संवेदना

एजेंसी

पेरिस/मैनचेस्टर। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में योम किप्पुर के अवसर पर सिनेगॉग (यहूदी उपासना स्थल) के बाहर हुए आतंकी हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इस हमले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह हमला कार चढ़ाने और चाकू से वार करने के जरिए किया गया। हमलावर को मौके पर मौजूद सशस्त्र अधिकारियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हमले ने ब्रिटेन समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता और आक्रोश पैदा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, फ्रांस मैनचेस्टर के सिनेगॉग में उपासकों पर हुए इस यहूदी-विरोधी आतंकी हमले से प्रभावित परिवारों, यहूदी समुदाय और ब्रिटिश जनता के साथ खड़ा है। मैक्रों ने आगे कहा, ÷योम किप्पुर के इस दिन हम दृढ़ संकल्प के साथ दोहराते हैं, यहूदी-विरोधी (एंटीसेमिटिज्म) के खिलाफ लड़ाई हमारी भी है और हम इसे बिना रुके जारी रखेंगे। घटना के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने अपनी डेनमार्क यात्रा बीच में ही छोड़ दी और समय से पहले यूके लौट रहे हैं। वे लंदन में सरकार की आपातकालीन कोबरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सुरक्षा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

वियतनाम में बुआलोई तूफान ने 51 लोगों की ली जान, 14 लोग अब भी लापता; 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर नुकसान का अनुमान

एजेंसी

हनोई । वियतनाम में तूफान बुआलोई और उसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज एजेंसी के अनुसार बुआलोई तूफान की चपेट में आने से मौत का आंकड़ा 51 तक पहुंच गया। 14 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि 164 लोग घायल हुए। वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को आपदा से जुड़ी एक रिपोर्ट साझा की। इसके अनुसार तूफान बुआलोई और उसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से उत्तरी और मध्य वियतनाम में 51 लोगों की मौत हो गई, 14 अन्य लापता हो गए और 164 लोग घायल हो गए। शुरुआती आर्थिक क्षति का अनुमान लगभग 15.9 ट्रिलियन वियतनामी डोंग (लगभग 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर) लगाया जा रहा है। इस तूफान में 238,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त या जलमग्न हो गए, लगभग 89,000 हेक्टेयर चावल और अन्य फसलें बर्बाद हो गईं। इसके अलावा, 17,000 हेक्टेयर से अधिक जलीय कृषि और लगभग 50,300 हेक्टेयर जंगलों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार, तूफान ने बुनियादी ढांचे को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, 8,800 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए और लगभग 468,500 घरों में अभी भी बिजली नहीं है। इसके साथ ही लगभग 1,500 स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय अधिकारी राहत कार्य जारी रखे हुए हैं, क्षतिग्रस्त

हुई सड़कों को साफ करने, सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने और प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए उपकरण जुटा रहे हैं। इस बीच, वियतनाम न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने गुरुवार को आपातकालीन राहत के लिए 15 प्रभावित इलाकों के लिए सहायता पैकेज को मंजूरी दी। इससे पहले, उन्होंने 30 सितंबर को स्थानीय अधिकारियों और विभागों को प्रभावित निवासियों की सहायता और प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों, पार्टी संगठनों, प्रशासन और आपदाओं से हुए नुकसान और कठिनाइयों को झेल रहे निवासियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई। उन्होंने जन समितियों के अध्यक्षों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द अलग-थलग पड़े इलाकों में पहुंचने के लिए सेना और वाहन जुटाएं। क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत करवाएं और प्रभावित निवासियों के लिए आश्रयों की व्यवस्था करें। इसके साथ ही उन्होंने 5 अक्टूबर से पहले क्षतिग्रस्त शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं की मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया है।

वियतनाम के कई हिस्सों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। उत्तरी मध्य वियतनाम के कई गांव जलमग्न हो गए थे और यातायात व बिजली गुल थी। बुआलोई एक हफ्ते में एशिया के लिए खतरा बनने वाला दूसरा बड़ा तूफान था। पिछले कई वर्षों में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक, रागासा तूफान ने उत्तरी फिलीपींस और ताइवान में कम से कम 28 लोगों की जान ले ली। इससे पहले कि यह चीन में पहुंचा और वियतनाम में फैल गया।

रिटर्न के मामले में शेयर बाजार से आगे निकला सोना, सोने की मदद से निवेशक हुए अमीर

एजेंसी

नई दिल्ली। सर्राफा बाजार में सोना लगातार मजबूती के नए रिकॉर्ड बना रहा है। खासकर साल 2025 में सोने की कीमत में जिस तरह तेजी का रुख बना है, उससे निवेशकों की कमाई में जमकर इजाफा हुआ है। सोने से मिलने वाले रिटर्न कि अगर स्टॉक मार्केट से मिलने वाले रिटर्न से तुलना करें, तो पिछले 5 साल की अवधि में इसने शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया है।सोने से मिलने वाले रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल की अवधि में इसकी कीमत में 200 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया है। इस तरह इस अवधि में सोना ने निवेशकों को करीब 24 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) के हिसाब से मुनाफा कराया है। दूसरी ओर, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट से मिलने वाले रिटर्न की ओर बात करें तो इस अवधि में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने निवेशकों को 17 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) के हिसाब से मुनाफा कराया है। 5 साल पहले 2020 में सोने की कीमत 39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब 1,17,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर चुकी है। सोने की कीमत में आई तेजी के कारण अब लोगों के उस नजरिये में भी बदलाव होना शुरू हो गया है, जिसमें सोना को सेफ इन्वेस्टमेंट तो माना जाता था।

विनट्रैक इंक के आरोपों की जांच करेगा केंद्रीय राजस्व विभागः वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चेन्नई की लॉजिस्टिक कंपनी विनट्रैक इंक के सीमा-शुल्क अधिकारियों पर लगाए आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। कंपनी के आरोपों की गहन जांच करने के लिए राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि चेन्नई सीमा शुल्क के खिलाफ विंट्रैक इंक के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि विनट्रैक इंक की तरफ से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की गहन जांच के लिए राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है। मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि सरकार ने मेसर्स विंट्रैक इंक (चेन्नई) द्वारा उठाए गए मामले का संज्ञान लिया है। वित?त मंत्रालय ने राजस्व विभाग (डीओआर) को वर्तमान मुद्दे की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य पर आधारित जांच करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने बताया कि राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विस्तृत तथ्यात्मक जांच करने, इससे संबंधित पक्षों और अधिकारियों की सुनवाई करने और सभी प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्यों की गहन जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। वित?त मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करदाता चार्टर को अपनाना, फेसलेस सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की शुरुआत और विवाद समाधान के लिए अपीलीय निकायों की स्थापना जैसी करदाता-अनुकूल पहलों की एक श्रृंखला लागू की है।

गोयल ने एयरबस के साथ की विमानन क्षेत्र में निवेश पर चर्चा

मुंबई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय विमानन निर्माता एयरबस के चेयरमैन रेने ओबरमैन के साथ भारत के विमानन क्षेत्र में अवसरों और वैश्विक एयरोस्पेस कंपनी के साथ सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट पर कहा कि अध्यक्ष रेने ओबरमैन के नेतृत्व में एयरबस बोर्ड का भारत में स्वागत किया।इस दौरान भारत में अपार अवसरों और एयरबस तथा भारत के विमानन क्षेत्र के बीच मजबूत, बढ़ती साझेदारी पर आकर्षक चर्चा हुई। गोयल ने एयरबस को भारत में सहयोग बढ़ाने और निवेश बढ़ाने की उनकी योजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र की ताकत और क्षमता का प्रमाण है, जो वैश्विक रुचि को आकर्षित रहा है। इस चर्चा को भारत के विमानन उद्योग को और मजबूत करने तथा एयरोस्पेस नवाचार एवं विनिर्माण के केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, पिछले साल एयर इंडिया ने 100 और एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया था, जिसमें 10 वाइडबॉडी ए350 और 90 नैरोबॉडी ए320 परिवार के विमान शामिल थे, जिनमें ए321ठ्ठद्भश्च भी शामिल था। 2023 में इंडिगो के बोर्ड ने 500 एयरबस ए320 परिवार के विमानों का भी ऑर्डर दिया, जो इसके इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर था।

गांधी जयंती, दशहरा पर बंद रहा शेयर बाजार, अब होगा कारोबार

मुंबई। गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर, विदेशी मुद्रा, सर्राफा और जिंस बाजार बंद रहा। इसके साथ ही देश के निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक बंद रहे। हालांकि, 03 अक्टूबर से शेयर बाजार में सामान्य तौर पर कारोबार शुरू होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में आज इक्विटी सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट और एसएलबी सेगमेंट तीनों बंद रहे। साथ ही करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं हुई। कमॉडिटी मार्केट भी सुबह और शाम दोनों सेशन के लिए बंद रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं हुआ। इसके अलावा शेयर बाजार में साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से शनिवार और रविवार को बंद रहेगा। शेयर बाजार में अगला अवकाश 21 अक्टूबर को दीपावली पर्व पर होगा। 22 अक्टूबर को प्रतिपदा और फिर 05 नवंबर को गुरुनानक जयंती पर शेयर बाजार में अवकाश रहेगा।

रबी फसलों की एमएसवैश्विक अनिश्चितताओं के बीच व्यापार एवं ऊर्जा असंतुलन भी चुनौतीः सीतारम

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे समय में जब विश्व की अर्थव्यवस्था संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है, तब भारत की बाहरी झटकों को झेलने की क्षमता मजबूत है। उन्होंने कहा कि देश को केवल वैश्विक अनिश्चितताओं से नहीं, बल्कि व्यापार एवं ऊर्जा असंतुलन से भी निपटना है। वित्त मंत्री ने यहां आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहे हैं, जबकि भारत 8 फीसदी सकल घरेलू उत?पाद (जीडीपी) वृद्धि की आकांक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को भारत में अवसर दिखने लगे हैं; पूंजीगत व्यय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कायम है। भारत में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए

अवसर दिखने लगे हैं, खासकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में रुचि बढ़ रही है। उन्होंने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें 8 फीसदी जीडीपी वृद्धि दर हासिल करनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक आत्मनिर्भरता के जरिए विकसित भारत बनने का मतलब यह नहीं है कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम अभूतपूर्व वैश्विक अस्थिरता के दौर में हैं। हालांकि, भारत में बाहरी झटकों को झेलने की मजबूत क्षमता है। सीतारमण ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8 फीसदी की विकास दर बनाए रखनी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चल रही वैश्विक उथल-पुथल का भारत की जीडीपी पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की विशेष सलाहकार एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग मारी एल्का पंगेस्तु और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष एवं कुलपति लैरी क्रेमर उपस्थित थे।

रुपये की मजबूती के लिए एक्टिव हुआ रिजर्व बैंक, डॉलर पर घटाई जाएगी निर्भरता

एजेंसी

नई दिल्ली। डॉलर की तुलना में रुपये की लगातार बढ़ रही कमजोरी के सिलसिले पर रोक लगाने, रुपये की स्थिति में सुधार लाने, रिजनल ट्रेडिंग में डॉलर पर निर्भरता कम करने और वैश्विक बाजार में डॉलर की जगह रुपये की स्थिति मजबूत करने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव हो गया है। डॉलर के साथ ही दुनिया की दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपये की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए रिजर्व बैंक एक साथ तीन उपायों पर काम शुरू करने जा रहा है। इन उपायों का उद्देश्य रीजनल ट्रेडिंग में डॉलर की निर्भरता को न्यूनतम करना (इनडायरेक्ट डीडॉलराइजेशन) और भुगतान माध्यम के रूप में रुपये को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित करना है। रिजर्व बैंक ने एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड) की बेंचमार्क लिस्ट में दुनिया की कुछ अन्य मुद्राओं को भी शामिल करने का फैसला किया है, जिससे भारतीय बैंक विदेशी मुद्रा जोड़ी (करेंसी पेयर्स) को सीधे कोट कर सकेंगे। ऐसा होने से डॉलर पर निर्भरता कम हो सकेगी, क्योंकि डॉलर के जरिए व्यापार होने पर भुगतान के दौरान होने वाले दोहरे रूपांतरण की वजह से लागत बढ़ने की समस्या भी कम हो पाएगी। भारतीय कंपनियां कई देशों में सीधे रुपये का लेनदेन करके कारोबार कर पाएंगी, जिससे कंपनियों की लागत भी घटेगी और भुगतान प्रक्रिया भी आसान हो सकेगी। ऐसा होने से रुपये को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूती भी मिल सकेगी। इसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (एसआरवीए) के तहत जमा राशि को कॉरपोरेट बॉन्ड्स या कॉमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति भी दे दी है। इस तरह से विदेशी निवेशकों को कॉरपोरेट बॉन्ड्स और कॉमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अधिक विकल्प मिल पाएगा।

मजबूत शुरुआत के बावजूद जिनकुशल इंडस्ट्रीज ने किया निराश, बिकवाली के दबाव में लगा लोअर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। कंस्ट्रक्शन मशीनरी का निर्यात करने वाली कंपनी जिनकुशल इंडस्ट्रीज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। हालांकि लिस्टिंग के बाद कुछ देर तक उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद कंपनी के शेयर गिर कर लोअर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 121 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग करीब 3 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 125 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से ये शेयर उछल कर 126.95 रुपये के स्तर तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद बिकवाली का दबाव बनने पर कंपनी के शेयर गिरकर 118.75 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक गिर गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 1.86 प्रतिशत का नुकसान हो गया। जिनकुशल इंडस्ट्रीज का 116.15 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 सितंबर के बीच

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 65.09 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 35.70 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 146.39 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 47.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 86,40,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 9,59,548 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं।

सर्राफा बाजार में तेजी जारी, सोना और चांदी की बढ़ी कीमत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,18,680 रुपये से लेकर 1,18,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,08,790 रुपये से लेकर 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। वहीं, चांदी के भाव में तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,53,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,18,830 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,18,680 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,08,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,18,730

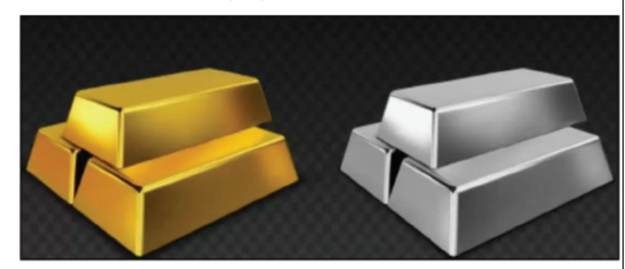

रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,08,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,18,680 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,08,790 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,18,680 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,08,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,18,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,18,730 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,08,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

स्टॉक मार्केट में टूऑल्ट बायोएनर्जी की मजबूत शुरुआत, फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनी टूऑल्ट बायोएनर्जी के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 496 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 10.88 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 550 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 10 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 545.40 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण इस शेयर की चाल में थोड़ी गिरावट भी गई। दोपहर 12 बजे तक का कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 532.20 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। टूऑल्ट बायोएनर्जी का 839.28 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 75.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी)

के लिए रिजर्व पोर्शन 165.16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 103.04 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 11.50 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 750 करोड़ रुपये के 1,51,20,967 करोड़ नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 89.28 करोड़ रुपये के 18 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ में नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने एथेनॉल प्लांट में मल्टी फीड स्टॉक ऑपरेशंस सेटअप करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की आय 2023-24 की आय 1,280.19 करोड़ रुपये की तुलना में 54 प्रतिशत बढ़ कर 1,968.53 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह कंपनी का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2024-25 में 361 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 146.64 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 31.81 करोड़ रुपये था। इसी तरह वित्त वर्ष 2024-25 में ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमॉर्टाइजेशन) 309.14 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

इंडिगो 26 अक्टूबर से फिर से शुरू करेगी कोलकाता-गुआंगझोउ उड़ानें

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच फिर से सीधी हवाई सेवा शुरू होने वाली हैं। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है, ये उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक शुरू हो सकती है। वहीं, विमानन कंपनी इंडिंगो ने चीन के ग्वांगझू के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इंडिगो ने जारी एक बयान में कहा कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ानें फिर शुरू करेगी। एयरलाइन ने कहा, 26 अक्टूबर 2025 से कोलकाता से ग्वांगझू (छ्वह्) को जोड़ने वाली मुख्यभूमि चीन के लिए दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानें फिर से शुरू होंगी। एयरलाइंस ने बताया कि नियामक अनुमोदन के अधीन, इंडिगो जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझू के बीच अपनी सीधी उड़ानें भी शुरू करेगी। इन उड़ानों के संचालन के लिए इंडिगो अपने एयरबस ए320ठ्ठद्भश्च विमान का उपयोग करेगी, जिससे सीमा पार व्यापार और रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारियों के अवसर फिर से स्थापित

होंगे और दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण निलंबित होने से पहले 2020 की शुरुआत तक दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा चालू थीं। भारतीय और चीनी एयरलाइनों की सीधी उड़ानें थीं। पूर्वी लद्दाख और सीमा विवाद के कारण भी ये सेवाएं निलंबित रहीं।

फ्लैट लिस्टिंग के बाद ईयरकार्ट के शेयरों में तेजी, मुनाफे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। हियरिंग ऐड्स और रिलेटेड एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी ईयरकार्ट लिमिटेड ने आज स्टॉक मार्केट में सांकेतिक बढ़त के साथ एंट्री की हालांकि लिस्टिंग के बाद खरीदारी शुरू हो जाने के कारण आईपीओ निवेशक फायदे में आ गए। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 135 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग सिर्फ 0.37 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 135.50 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद हुई लिवाली के कारण कंपनी के शेयर थोड़ी देर में ही 142.25 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 5.37 प्रतिशत का मुनाफा हो गया। ईयरकार्ट लिमिटेड का 49.26 करोड़ रुपये का

आईपीओ 25 से 29 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.28 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.63 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन सिर्फ 0.35 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 31,30,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 3,34,000 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ में नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 1.31 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 3.06 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 6.88 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार पर दबाव, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार की मिली-जुली शुरुआत हुई थी। सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुलने में सफल रहा था, जबकि निफ्टी ने कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत की थी। बाजार खुलने के बाद बिकवाली के दबाव के कारण शेयर बाजार में तेज गिरावट आ गई। हालांकि पहले 15 मिनट के कारोबार के बाद ही खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में सुधार होने लगा। पहले 1 घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.12 प्रतिशत और निफ्टी 0.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती 1 घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 3.36 प्रतिशत से लेकर 1.69 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, मैक्स हेल्थ केयर, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ओएनजीसी के शेयर 2.08 प्रतिशत से लेकर 0.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,518 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1,626 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में

कारोबार कर रहे थे, जबकि 892 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 13 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे।

विकसित भारत के लिए आर्थिक वद्धि तेज करनी होगी, पूंजी निवेश बढ़ाना होगाःएनके सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। आर्थिक विशेषज्ञ एवं पूर्व आईएएस एन.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए साल दर साल आठ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल करनी होगी और पूंजीगत व्यय में और वृद्धि करनी होगी। श्री सिंह यहां चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में आर्थिक वृद्धि दर मजबूत नीतिगत आर्थिक सुधारों से सुधरी है। इसके साथ ही जनसंख्या वद्धि दर कम होने के मिले जुले लाभ से प्रतिव्यक्ति आय दो गुनी हो गयी है। श्री सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय का स्तर बढ़ाने, मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच तालमेल बिठाये रखने, व्यापार को वृद्धि के इंजन के रूप में बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने, सुधारों को राज्यों के स्तर पर फैलाने तथा नयी उभरती वैश्विक परिस्थितियों में चुनौतियों तथा विडंबनाओं को अवसर बनाने पर ध्यान देने की सिफारिश की। बाद में उन्होंने संवादाताओं से बातचीत करते हुए कहा, 'भारत का विशाल घरेलू बाजार अभी अतृप्त है जहां प्रति व्यक्ति आय अब पांच से छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है।

स्टॉक मार्केट में तेलगे प्रोजेक्ट्स की मजबूत शुरुआत, फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज का कारोबार करने वाली कंपनी तेलगे प्रोजेक्ट्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी के साथ एंट्री करके अपने कारोबार की शुरुआत की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 105 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 3 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 108.10 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद हुई लिवाली के कारण कंपनी के शेयर उछल कर 112 रुपये तक पहुंचे, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली के ये ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसल भी गया। सुबह 11:30 बजे तक कारोबार होने के बाद तेलगे प्रोजेक्ट्स के शेयर 110.85 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। तेलगे प्रोजेक्ट्स का 27.24 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 2.99 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 5.41 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 2.75 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.72 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 25,94,400 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 90 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 2.66 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 5.38 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 105 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 25.65 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इस दौरान कंपनी पर कर्ज के बोझ में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 2.50 करोड़ रुपये, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 2.76 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज उछल कर 9.38 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें, तो वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी में ये 1.09 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी में बढ़ कर 3.66 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी में उछल कर 10.31 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

अनन्या-तृप्ति और शरवरी वाघ के बीच कांटे की टक्कर! इस बड़ी फिल्म में किसकी होगी एंट्री?

सिर्फ साउथ ही नहीं, बल्कि कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों पर काम चल रहा है. जो अगले साल या फिर उसके बाद रिलीज की जाएंगी. यूं तो कुछ पिक्चरों का ऐलान किया जा चुका है. जबकि, कुछ अब भी चर्चा में बनी है. हर साल कई फिल्मों के सीक्वल देखने को मिलते हैं. इस वक्त भी कई बड़ी फिल्मों के सीक्वल पर चर्चा है, जिसमें से एक है- साल 2001 में आई फिल्म. जिसमें तबू ने अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया था. मधुर भंडारकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. तबू के अलावा अतुल कुलकर्णी भी अहम किरदार में थे. अब उस फिल्म के सीक्वल के लिए अनन्या, तृप्ति और शरवरी का नाम सामने आ रहा है.दरअसल इस फिल्म का नाम है 'चांदनी बार', जिसमें तबू छा गई थीं. उनका परफॉर्मेंस इतना दमदार था कि सबने प्यार बरसाया था. हालांकि, इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अब भी कन्फ्यूजन बना हुआ है. खासकर लीड रोल में किस एक्ट्रेस को फाइनल किया जाएगा, यह लगातार सवाल बना हुआ है. क्यों इन तीनों के नाम पर अटके हैं मेकर्स?

'चांदनी बार 2' में कौन होगी?

हाल ही में एक वेबसाइट पर नई रिपोर्ट छपी. जिससे पता लगा कि शरवरी वाघ, अनन्या पांडे और तृप्ति डिमरी में से एक को चुना जाएगा. पर जिस तरह से तीनों ने पिछली फिल्मों में परफॉर्म किया है, मेकर्स कन्फ्यूज हैं. इस रोल के लिए तीनों में से कौन सी एक्ट्रेस परफेक्ट रहेंगी? दरअसल इस रोल के लिए इमोशनल गहराई की जरूरत है, जिसके लिए शरवरी परफेक्ट हैं. जो दमदार किरदारों को बखूबी निभाने के लिए जानी जाती हैं. अनन्या पांडे को चुनने का इसलिए फायदा है कि वो रोल में नयापन ला सकती हैं.साथ ही तृप्ति डिमरी, जो रातों-रात नेशनल क्रश बन गई थीं. वो भी इस किरदार के लिए मजबूत दावेदार रही हैं. दरअसल इस ओरिजनल फिल्म में तबू ने Mumtaz Sawant का किरदार निभाया था. अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं. हालांकि, नई फिल्म में एक नई जनरेशन को दिखाया जाएगा. पर क्या सीक्वल में तबू भी होंगी, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. दरअसल तबू वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. जिसने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई की थी.

नींद में थे अभिषेक, फरहाना ने फेंका पानी तो हो गया बवाल, बोलीं- कैप्टन हूं, जो चाहूंगी करूंगी

'बिग बॉस 19' का घर हर दिन नए हंगामे का अखाड़ा बन रहा है. हाल ही में बिग बॉस के घर की कैप्टन बनीं फरहाना भट्ट ने जिस तरह से घर चलाया है, उस पर अब कंटेस्टेंट्स ने पलटवार करना शुरू कर दिया है. जल्द ही फरहाना और अभिषेक बजाज के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत कैप्टन के एक हैरान करने वाले एक्शन से होगी.लाइव फीड के मुताबिक कैप्टन फरहाना ने अभिषेक बजाज के सोते हुए उनके चेहरे पर पानी छिड़क दिया. जब अभिषेक उठे, तब उन्होंने फरहाना को ये कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें बार-बार जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया. और मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूं, क्योंकि मैं कैप्टन हूं. फरहाना की इस हरकत के तुरंत बाद अशनूर कौर अभिषेक का बचाव करने सामने आईं.

अशनूर पर भी फूटा फरहाना का गुस्सा

अशनूर को अभिषेक का साथ देता हुआ देख, फरहाना ने गुस्से में अशनूर को अभिषेक की वॉचमैन कह दिया. उनके इस बर्ताव से तीनों के बीच झगड़े की आग और भड़क गई.

अभिषेक ने दी खुली चेतावनी

फरहाना की इस हरकत पर अभिषेक बजाज ने सीधे-सीधे चेतावनी देते हुए कहा, मैंने एक बाल्टी उसके ऊपर नहीं मारी तो मेरा नाम बजाज नहीं. अभिषेक के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले एपिसोड में पानी फेंककर इसका बदला जरूर लेंगे.

अशनूर की परवरिश पर उठाए सवाल

दरअसल अशनूर और फरहाना के बीच की दुश्मनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. इस रियलिटी शो के लेटेस्ट प्रोमो में, बिग बॉस ने फरहाना को सभी कंटेस्टेंट्स को उनके योगदान के आधार पर रैंक करने के लिए कहा. रैंकिंग के दौरान फरहाना ने अशनूर को नकली और पाखंडी (फेक और हिपोक्रेट) बताया. बात तब और बिगड़ गई जब फरहाना ने अशनूर की परवरिश पर ही सवाल उठा दिए. अशनूर ने इसका ज़ोरदार बचाव किया और कहा कि वो नकली नहीं हैं और उन्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है.

इस एक्टर ने काटा अमिताभ बच्चन के नाती का पत्ता! सामने हैं अक्षय कुमार की भांजी

हर साल कई स्टार किड्स फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं. जहां कुछ की पहली ही फिल्म धमाल मचा देती हैं, तो कुछ बुरी तरह पिट जाते हैं. आज जिस बड़ी फिल्म की बात हो रही है, उसे मैडॉक फिल्म्स वाले बना रहे हैं. लंबे वक्त से ऐसी चर्चा है कि राजेश खन्ना की नातिन Naomika Saran जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. जी हां, रिंकी खन्ना की बेटी और अक्षय-ट्विंकल खन्ना की भांजी का नाम चर्चा में बना है. पर उनके सामने इस फिल्म में एक न्यू कमर ही था. जो ओटीटी से अपना डेब्यू कर चुका है. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य का किसने पत्ता काट दिया है ?कुछ वक्त पहले ही जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से कई स्टार किड्स ने अपना डेब्य किया. इसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान, श्रीदेवी की लाडली खुशी कपूर, अमिताभ बच्चन के नाती आगस्त्य नंदा समेत वेदांग रैना भी शामिल थे. कुछ वक्त से ऐसी खबर है कि रिंकी खन्ना की बेटी नाओमीका सरन की डेब्यू फिल्म में अगस्त्य होंगे. पर उनका पत्ता कटने की जानकारी मिल रही है.

बिग बी के नाती का किसने काटा पत्ता?

हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट पर रिपोर्ट छपी. जिससे पता लगा कि नाओमीका लगातार मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में स्पॉट की जा रही हैं. वहीं उनके अलावा अगस्त्य नंदा भी दिखाई दिए थे. दिनेश विजन की रोमांटिक कॉमेडी से दोनों को लॉन्च करने की तैयारी भी थी. पर कास्टिंग ने अब अलग मोड़ ले लिया है. कहा जा रहा है कि अगस्त्य की जगह फिल्म में वेदांग रैना की एंट्री हुई है. जिन्होंने अपने दोस्त का ही फिल्म से पत्ता काट दिया है. वो इस प्रोजेक्ट में बतौर लीड नजर आएंगे.

दरअसल यह एक रोमांटिक एंटरटेनर होने वाली है. जिसे Jagdeep Sidhu डायरेक्ट कर रहे हैं. जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में खूब धमाल मचा चुके हैं. उन्होंने किस्मत, जट्ट एंड जूलियट 3 समेत कई फिल्में बनाई हैं. वो एकदम फ्रेश कास्ट के साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं. यह एक खूबसूरत बैकड्राप पर बनी फिल्म होगी. जिसे हिमाचल प्रदेश की वादियों में शूट करने की खबरें सामने आ रही हैं.

कौन हैं नाओमिका सरन?

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की छोटी बेटी रिंकी की बेटी हैं नाओमिका सरन. रिंकी खन्ना ने 8 फरवरी 2003 को बिजनेसमैन समीर सरन से शादी की थी. नाओमिका को लेकर चर्चा है कि जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. राजेश खन्ना की नातिन की एंट्री के लिए हर कोई एक्साइटेड है.

उसे खुद पहचान बनानी होगी...बेटी आदिरा को कैमरे से दूर रखने की रानी मुखर्जी ने बताई वजह

रानी मुखर्जी अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं. उन्हें बेहद कम ही अपने फिल्ममेकर पति आदित्य चोपड़ा और बेटी आदिरा के बारे में बात करते हुए देखा जाता है. एक्ट्रेस अपनी बेटी को भी कैमरों से दूर ही रखती हैं. रानी ने आज तक ना तो अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं और नाही उन्होंने बेटी आदिरा की कोई तस्वीर पोस्ट की है. वह अपने परिवार को कैमरों से दूर रखना ही पसंद करती हैं.ANI के पॉडकास्ट में रानी मुखर्जी ने बेटी को कैमरों से दूर रखने के पीछे की वजह बताई और उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि वह और आदित्य अपनी बेटी को मीडिया की चकाचौंध से दूर इस रखते हैं, ताकि वह अपना बचपन जी पाएं. रानी ने बताया,हमारी बेटी के लिए भी यही सोच है. हम नहीं चाहते थे कि वह कभी ऐसी स्थिति में आए जहां उसे ज़्यादा एक्सपोज किया जाए. उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसके साथ कुछ खास हो रहा है.

पहचान खुद हासिल करनी होगी - रानी

पर्दे पर लगातार सशक्त महिलाओं की कहानियों को आगे बढ़ाने वाली रानी का मानना है कि उनकी बेटी को दुनिया में अपनी जगह अपनी शर्तों पर बनानी चाहिए. रानी ने कहा, क्योंकि जब वह बड़ी होगी, जब वह अपना करियर प्रोफेशन चुनेगी, तो वह जो भी पहचान हासिल करेगी, वह उसकी योग्यता से ही मिलेगी. उसे यह पहचान इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि उसके माता-पिता मशहूर हैं. उसे यह पहचान खुद हासिल करनी चाहिए.

उसे यह यूं ही नहीं मिलनी चाहिए.उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेसी के मामले में आदिरा अपने पिता आदित्य चोपड़ा से काफी मिलती-जुलती हैं और उनका नजरिया पहले से ही मजबूत है. रानी के मुताबिक यह गुण भविष्य में उनकी बेटी के लिए बेहद मददगार साबित होगा, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहना और अभिव्यक्त करना सीख रही है.

रानी और आदित्य ने की शादी

रानी और आदित्य ने साल 2014 में शादी की थी और शादी के एक साल बाद ही उनकी बेटी आदिरा का जन्म हुआ था. रानी की पॉपुलैरिटी के बावजूद इस जोड़े ने अपनी बेटी को मीडिया की नजरों से दूर रखने में कामयाबी हासिल की है, जिससे वह स्टारडम के दबाव के बिना बड़ी हो रही हैं.

दशहरे पर श्री राम रामलीला ट्रस्ट द्वारा नांगलोई क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई

शिवानी कौर

दिव्य दिल्ली। पूरे देश में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया, और इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में श्री राम रामलीला ट्रस्ट द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा नांगलोई स्थित परशुराम धर्मशाला से आरंभ होकर शिव राम पार्क होते हुए करण वाटिका तक निकाली गई। यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, रावण और काली माता की जीवंत और सजीव झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस आयोजन की अगुवाई ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित गौड़ ने की। उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष महेश दत्त भारद्वाज, महासचिव राकेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष सौरभ गुप्ता, उपाध्यक्ष अनिल कुमार, कपिल शर्मा तथा अन्य पदाधिकारीगण भी यात्रा में सम्मिलित हुए और भगवान श्री राम की यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। रामलीला मंचन के अवसर पर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को सह परिवार सहित सम्मानित किया गया।

इस विशेष आयोजन में काली माता की झांकी ने विशेष रूप से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। शक्ति की प्रतीक यह झांकी भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बनी रही। पूरे मार्ग में स्थानीय निवासियों ने झांकियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और धार्मिक भावना से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। यह शोभायात्रा क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक एकता का प्रतीक बनी। श्री राम रामलीला ट्रस्ट द्वारा किया गया यह आयोजन न केवल धर्म और संस्कृति का प्रचार है, बल्कि युवा पीढ़ी को भारतीय मूल्यों और परंपराओं से जोड़ने का प्रयास भी है।

जीएच-6 में हुआ मां दुर्गा का विसर्जन, सिंदूर खेला, ढोल-नगाड़े और भक्ति से गूंजा वातावरण

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। दशहरे के पावन अवसर पर जहां पूरे देश में रावण दहन के साथ विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, वहीं राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित जीएच-6 सोसाइटी में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस पांच दिवसीय समारोह का नेतृत्व साधना शर्मा, बबीता शर्मा और मंजू शर्मा ने किया, जिसे पश्चिम विहार नवरात्रि पूजा समिति के सहयोग से संपन्न कराया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन नजर आए। पूजा के अंतिम दिन मां दुर्गा की भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसके बाद महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर 'सिंदूर खेला' की परंपरा निभाई। ढोल-नगाड़ों और जयकारों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा पश्चिम विहार से प्रारंभ होकर निहाल विहार स्थित छठ घाट तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने मां को विदाई दी और अगले वर्ष पुनः आने का निमंत्रण दिया। पूरे आयोजन में क्षेत्रीय लोगों की भागीदारी सराहनीय रही, जिसने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं लोगों को जोड़ने का कार्य करती हैं।

"एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल: हक, अस्मिता और आर-पार की लड़ाई"

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। "दिल्ली की सफाई व्यवस्था और मच्छरों की रोकथाम का जिम्मा उठाने वाले एमसीडी के डीबीसी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 29 सितंबर से शुरू हुई यह हड़ताल लगातार जारी है। सिविक सेंटर गेट नंबर 5 के बाहर कर्मचारी दिन-रात डटे हुए हैं। सवाल ये है कि कर्मचारियों और प्रशासन के बीच टकराव की ये लड़ाई आखिर कब खत्म होगी?" "हड़ताली कर्मचारी कहते हैं कि उनकी मांगें नई नहीं हैं। समान वेतन, मेडिकल लीव और अनुकंपा नियुक्ति जैसी बुनियादी मांगें वो पिछले 30 साल से उठाते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि निगम सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। अब हालात ये हैं कि मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है।" यूनियन नेता कहते हैं कि हम दिन-रात जनता की सेवा करते हैं। बीमारियों से लड़ते हैं। लेकिन जब हमें खुद हक की जरूरत होती है तो हमें सिर्फ टाल दिया जाता है, 30 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। आज कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सिविक सेंटर के चारों ओर मार्च निकाला। पोस्टर और नारों के साथ उन्होंने प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निगम ने कभी गंभीरता से उनकी मांगें नहीं सुनीं। यहां तक कि हड़ताल शुरू होने के बाद भी एमसीडी प्रशासन ने अब तक उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। एक महिला कर्मचारी ने कहा कि हम अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली की गलियों में काम करते हैं। लेकिन जब हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है तो कोई सुनवाई नहीं होती। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। धरना स्थल पर कर्मचारी डटे हुए हैं। कोई पोस्टर बना रहा है, कोई नारे लिख रहा है, तो कोई प्रशासन को चेतावनी दे रहा है। साफ है कि अब ये आंदोलन केवल मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की अस्मिता का सवाल बन चुका है। बारिश और धूप के बावजूद कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं। यूनियन नेताओं का कहना है कि निगम की बेरुखी और चुप्पी ने ही इस आंदोलन को लंबा खींच दिया है। अगर उनकी मांगों पर समय रहते सुनवाई हो जाती तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। अब कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं, लेकिन निगम ने हमारी अनदेखी की। अब हम हिलने वाले नहीं हैं। चाहे कितने भी दिन क्यों न लगें, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं हम धरना खत्म नहीं करेंगे। धरने पर बैठे कर्मचारी एक स्वर में कहते हैं कि अब आर-पार की लड़ाई होगी। उनकी आवाज और उनका गुस्सा लगातार बुलंद हो रहा है। प्रशासन चुप है, निगम खामोश है और सरकार अब तक दूर खड़ी है। लेकिन इस चुप्पी ने आंदोलन को और मजबूत कर दिया है। कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन अपनी चुप्पी साधे हुए है। यह टकराव कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जब तक उनकी आवाज सुनी नहीं जाती, यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है।

संत निरंकारी मिशन को मानव सेवा में अद्वितीय योगदान हेतु विशेष सम्मान

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली:- गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2025 को इंटरनेशनल होटल, श्रीनगर में गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पद्मश्री डॉ. एस. पी. वर्मा ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सिद्धांतों और विचारों को पुनः स्मरण करना था। इस गरिमामय आयोजन में कई प्रतिष्ठित संस्थाओं की सहभागिता रही, जिनमें संत निरंकारी मिशन का प्रतिनिधित्व करते हुए संत निरंकारी मंडल के सचिव श्री जोगिंदर सुखीजा जी की सम्मानजनक उपस्थिति रहीं। सुखीजा ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने संबोधन में संत निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांत- ॒मानव को मानव हो प्यारा, इक-दूजे का बने सहारा॑ को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार निरंकारी मिशन विश्वबंधुत्व, एकता और आपसी भाईचारे के भाव को सशक्त रूप से प्रसारित कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आगामी निरंकारी संत समागम जो 31 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2025 तक संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल, समालखा (हरियाणा) में आयोजित होने जा रहा है उसके लिए आमंत्रित किया और कहा कि ॒संत समागम वह आध्यात्मिक मंच है, जहाँ समस्त धर्म, जाति और वर्गों के लोग एकत्रित होकर प्रेम, एकता और भाईचारे का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह आयोजन मानवता के सच्चे स्वरूप को उजागर करता है। मानवता की निःस्वार्थ सेवा के पथ पर अग्रसर संत निरंकारी मिशन, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में समाज कल्याण हेतु निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। मिशन द्वारा संचालित यह सेवा ॒समस्त संसार एक परिवार॑ की भावना को साकार करने का एक सशक्त प्रयास है। मिशन की सामाजिक शाखा, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा समय-समय पर अनेक सामाजिक कार्य आयोजित किये जाते हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, रक्तदान, स्वच्छता अभियान तथा आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में संपूर्ण भारतवर्ष में अनुकरणीय कार्य कर रही है। जम्मू और कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, बादल फटना और ऑपरेशन सिंदूर के समय, मिशन ने अत्यंत संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ राहत कार्यों में भागीदारी की। प्रभावित परिवारों तक खाद्य सामग्री, औषधियाँ एवं आवश्यक सहायता पहुँचाकर मिशन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि वह मानव सेवा के प्रत्येक कार्य पर सजग और सक्रिय है। इन सेवाओं की व्यापक सराहना समाज के विभिन्न वर्गों के साथ-साथ सरकार द्वारा भी की गई। इसी क्रम में, श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में जम्मू एवं कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने संत निरंकारी मंडल के सचिव श्री जोगिंदर सुखीजा को मिशन की इस निःस्वार्थ सेवा हेतु विशेष सम्मान प्रदान किया। सम्मान ग्रहण करते हुए श्री जोगिंदर सुखीजा ने कहा कि संत निरंकारी मिशन, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से सदैव समाज कल्याण और मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा हर प्रयास सेवा, समर्पण और एकत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। चाहे प्राकृतिक आपदाओं में राहत हो या रक्तदान जैसे जीवनदायिनी अभियानों में सहभागिता, मिशन सदैव अग्रणी रहा है। हमारा उद्देश्य है -प्रत्येक मानव तक प्रेम, शांति और एकता का संदेश पहुँचाना॑ निःसंदेह गांधी जयंती के इस स्मरणीय अवसर पर संत निरंकारी मिशन की सहभागिता एवं उसे प्राप्त सम्मान, दोनों ही समाज के प्रति उसके समर्पण, निष्काम सेवा और विश्वबंधुत्व की भावना के उज्ज्वल प्रतीक हैं। यह मिशन आज भी उसी आदर्श पथ पर अग्रसर है, जहां मानवता सर्वोपरि है।

तुलसीपुर में करंट लगने से मां-बेटी की मौत

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तुलसीपुर नगर के मिल चौराहे पर करंट लगने से मां-बेटी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय बेबी और उनकी 15 वर्षीय बेटी छाया के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

मृतका बेबी अपने मायके में रहकर एक होटल चला रही थीं। उनके पति मुंबई में मजदूरी करते हैं। बेबी अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। मृतका की मां सावरी देवी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी पचपेड़वा के खाखरा में हुई थी। पति के मुंबई जाने के बाद वह कुछ समय से मायके में रहकर होटल चला रही थीं। रोजाना की तरह वह अपनी बेटी छाया के साथ होटल पर ही रहती थीं। सुबह जब बेबी के पिता होटल खोलने के लिए मटर लेकर पहुंचे, तो दुकान बंद मिली। आवाज देने पर दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया गया। अंदर मां-बेटी मृत अवस्था में एक-दूसरे से लिपटी पड़ी थीं और उनके ऊपर एक स्टैंड वाला पंखा गिरा हुआ था। कमरे के एक कोने में एक छोटा बच्चा सहमा हुआ दुबका था।

परिजनों ने बताया कि होटल का सामान भी बिखरा पड़ा था और होटल में काम करने वाला नौकर मौके से गायब मिला। मामले को लेकर तुलसीपुर प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया की प्रथम दृष्टि करंट लगने से मौत हई है । शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है। परिजनों के तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

दिल्ली के पश्चिम विहार में बांगिया परिषद और बंगाली एसोसिएशन द्वारा भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र स्थित निवेदिता एनक्लेव में बांगिया परिषद पश्चिम विहार द्वारा पारंपरिक श्रद्धा और सांस्कृतिक भव्यता के साथ माँ दुर्गा की पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सफलता में संजय घोषाल, तामोजित चक्रवर्ती, अदिति चक्रवर्ती सहित समिति के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा। पूजा महोत्सव के दौरान माँ दुर्गा की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कलाकारों, प्रसिद्ध गायकों और सामाजिक हस्तियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गौरवमयी बना दिया। समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। महोत्सव में बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली – पारंपरिक सजावट, वाद्य यंत्रों की धुन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन की मुख्य आकर्षण रहीं। इसी क्रम में पश्चिम विहार बंगाली एसोसिएशन द्वारा भी एक और भव्य दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संजय घोषाल, मनोजीत मुखर्जी और सौरभ सहित एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही।इस समारोह की विशेष बात यह रही कि इंडियन आइडल जैसे लोकप्रिय मंच से जुड़े गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बंगाली और हिंदी गीतों की मधुर स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। साथ ही, बंगाल के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने के लिए भी श्रद्धालु उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। दोनों आयोजनों में न केवल स्थानीय निवासी बल्कि दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का आनंद लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामुदायिक सहयोग की मिसाल भी बना।

पश्चिम विहार में ब्रह्माकुमारीज का संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था कार्यक्रम आयोजित

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। दिल्ली के पश्चिम विहार ए-3 में प्रजापति ब्रह्मा कुमारीस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार के सौजन्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भूतपूर्व पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के बीच की दूरी को हटाने और एकजुटता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर बी.के. ई.वी. गिरीश, बी.के. वीरेंद्र भाई, बी.के. सुषमा दीदी और सरिता दीदी के मार्गदर्शन एवं योगदान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। बुजुर्ग जनों को विशेष रूप से सम्मानित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान को सलाम किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं, जिन्होंने सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। इस पहल से विभिन्न पीढ़ियों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने में मदद मिली। ब्राह्माकुमारीज ने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में वृद्धजनों के प्रति सम्मान और उनके अनुभवों को साझा करने की भावना को प्रोत्साहित किया।

बड़ौत में छात्र की हत्या, परिसर में पड़ा मिला शव

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक कॉलेज में छात्र का शव मिला है। शरीर पर चोट के निशान हैं, हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है।

गुरुवार के दिन बड़ौत पुलिस को सूचना मिली थी की जनता वेदिक डिग्री कॉलेज के डेरी विभाग के पास एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान संयम पुत्र वीरेंद्र निवासी बावली के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दी गई और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बड़ौत कोतवाली पर शिकायत दी है। बड़ौत पुलिस का कहना है कि छात्र के हाथों पर पट्टियां और शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य उठाए गए हैं।
सीओ विजय चौधरी का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अर्थव्यवस्था का नया चेहरा

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। तकनीकी क्रांति के इस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गेमचेंजर के रूप में उभर रही है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक अक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान दे सकता है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि आने वाले वर्षों में अकका महत्व कितना व्यापक और प्रभावशाली होने वाला है। उद्योग और उत्पादन के क्षेत्र में अक का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्वचालन के कारण उत्पादन लागत में 20-30% तक की कमी आई है, वहीं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत जैसे विकासशील देश भी इस बदलाव की धारा से अछूते नहीं हैं। एग्रीटेक कंपनियाँ फसल पूर्वानुमान और सप्लाई चेन प्रबंधन में अक का सफल उपयोग कर रही हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य और बेहतर सुविधाएँ मिल रही हैं। अक का प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में दोहरा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (क्छड) के अनुसार, आने वाले 5 वर्षों में लगभग 40% पारंपरिक नौकरियाँ स्वचालन के चलते बदल सकती हैं। हालांकि, इसके समानांतर अक, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे उभरते क्षेत्रों में नई नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में अक-आधारित नौकरियों में पिछले वर्ष लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र की संभावनाओं को दशार्ता है। अक अब केवल तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा। वित्तीय सेवाओं में धोखाधड़ी रोकने और जोखिम विश्लेषण के लिए बैंक अक एल्गोरिद्म का उपयोग कर रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियाँ उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतों का विश्लेषण कर बिक्री में 10झ15% तक की वृद्धि दर्ज कर रही हैं। इससे व्यापारिक निर्णय अधिक सटीक और डेटा-आधारित बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सरकारें समय रहते शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश करें, तो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अकयुग में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकती हैं। अन्यथा, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता की चुनौतियाँ और गहरी हो सकती हैं।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321